सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

खुशी और गम एक दूसरे के समांतर चलते हैं जब एक शांत होता है तो दूसरा भी शिथिल पड़ जाता है

वर्ष 01, अंक 250, नई दिल्ली

बुधवार, 22 नवम्बर 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

दिल्ली में चलेंगी एप आधारित प्रीमियम बसें

नई नीति के तहत ई-बसों की लाइसेंस फीस होगी माफ

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस योजना को दिल्ली के एलजी ने अपनी मंजूरी दे दी थी।

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस योजना को दिल्ली के एलजी ने अपनी मंजूरी दे दी थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को क्रांतिकारी बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में इसे एक बड़ा बदलाव बताया। केजरीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा, ₹मुझे उम्मीद है यह सेवा दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। लोग अपनी कार और स्कूटर छोड़कर बसों में सफर करना शुरू करेंगे।

दिल्ली परिवहन विभाग ने बसों की प्री-बुकिंग और एग्रीगेशन का रास्ता साफ करने के लिए अपनी प्रीमियम बस एग्रीगेटर नीति जारी की। नए नियम दिल्ली के क्षेत्र में प्रीमियम बसों की लाइसेंसिंग और उनके संचालन को नियंत्रित करेंगे।

अधिसूचना में एक एग्रीगेटर को ₹परिवहन के उद्देश्य से ड्राइवर के साथ जुड़ने के लिए एक डिजिटल मध्यस्थ या बेड़े के मालिक या यात्री के लिए बाजार₹ के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक व्यक्ति/इकाई हो सकता है, या तो बेड़े का मालिक या ऑपरेटर, जिसका कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट धारक के साथ संपूर्ण वाहन के इस्तेमाल के लिए समझौता है, न कि उसके किसी हिस्से के लिए।

परिवहन विभाग ने प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इंसेंटिव दिया। नई नीति के आदेश के अनुसार, 1 जनवरी, 2025 से योजना के तहत दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों के पंजीकरण की अनुमति होगी, जिसमें सीएनजी बसों या अन्य श्रेणी की बसों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना 2023 के अनुसार, लाइसेंस धारक को लाइसेंस मिलने की तारीख से 90 दिनों के भीतर कम से कम 25 प्रीमियम बसों का बेड़ा चालू रखना होगा। लाइसेंस पांच साल की अवधि के लिए वैध होगा।

नियम के मुताबिक, ₹इस योजना के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय लाइसेंस धारक के पास सार्वजनिक परिवहन / शेयर्ड ट्रांसपोर्ट में वाहनों के संचालन / प्रबंधन / संचालन के लिए कम से कम 3 वर्षों का अनिवार्य अनुभव होना चाहिए। साथ ही निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताओं के दौरान न्यूनतम 100 यात्री बसों का बेड़ा होना चाहिए। पिछले तीन वित्तीय वर्षों (प्रत्येक वर्ष), पिछले तीन वित्तीय वर्षों (प्रत्येक वर्ष) के दौरान न्यूनतम 1000 यात्री कारों का बेड़ा या यात्री कारों और बसों के मिश्रित बेड़े के मामले में, कुल न्यूनतम बेड़ा कम से कम 100 बसों के बराबर होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, 10 कारों को 1 बस के बराबर माना जाएगा।₹

नियमों में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक प्रीमियम बसों को लाइसेंस फीस से छूट दी जाएगी। दूसरी ओर, नियमों में कहा गया है कि लाइसेंस अनुदान के लिए, ई-बस खिलाड़ियों के अलावा अन्य आवेदकों को कुल 5 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, उन्हें 100 बसों के लिए 1 लाख रुपये, 1000 बसों के लिए 2.5 लाख रुपये और 1000 से ज्यादा बसों के लिए 5 लाख रुपये की ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा राशि भी देनी होगी।

इसने लाइसेंसधारियों को रूट और किराया तय करने की भी अनुमति दी। हालांकि, उसने किराया सीमा पर फैसले में कुछ शर्तें रखी हैं।

नियमों में कहा गया है, ₹लाइसेंस धारक किसी भी रूट/गंतव्य के लिए उपयुक्त किराया संरचना निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा। आम जनता की जानकारी के लिए किराया मोबाइल और वेब-आधारित एप्लिकेशन पर प्रदर्शित किया जाएगा। डायनैमिक प्राइसिंग (गतिशील मूल्य निर्धारण) की अनुमति होगी। बशर्ते कि आधार किराया दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) वातानुकूलित बसों के अधिकतम किराये से कम न हो। सिर्फ पहले से बुक की गई डिजिटल टिकटिंग की अनुमति होगी और कोई भौतिक टिकट जारी नहीं किया जाएगा।

गाजियाबाद में यूपी रोडवेज की 429 बसों में लगाए जाएंगे वाहन ट्रैकिंग उपकरण

परिवहन विशेष न्यूज

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) (UPSRTC) की बसों को खास तौर पर महिला यात्रियों के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए, राज्य भर में लगभग 5,000 बसों के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) (VLTD) लगाने की एक परियोजना शुरू की गई है।

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) (UPSRTC) की बसों को खास तौर पर महिला यात्रियों के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए, राज्य भर में लगभग 5,000 बसों के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) (VLTD) लगाने की एक परियोजना शुरू की गई है। इमें गाजियाबाद क्षेत्र की 429 बसें भी शामिल हैं।

यूपीएसआरटीसी के अधिकारियों ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार के निर्भया फंड द्वारा समर्थित है। और इसका मकसद बसों में महिला सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करना और बसों की लाइव ट्रैकिंग जैसी टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन के साथ यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाना है।

यूपीएसआरटीसी गाजियाबाद क्षेत्र के अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में 429 बसों की पहचान की गई है और अब तक 286 बसों में इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। गाजियाबाद क्षेत्र में कुल मिलाकर 967 बसें संचालित होती हैं।

यूपीएसआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक केसरी नंदन चौधरी ने कहा, ₹वीएलटीडी लगाने का काम शुरू हो गया है और क्षेत्र की 429 बसों में से 286 को अब तक कवर किया जा चुका है। परियोजना में अन्य कंपोनेंट्स हैं जैसे पैनिक बटन लगाना, नए वाहनों का इंटीग्रेशन जो इन उपकरणों से लैस हैं। और यात्रियों की जानकारी के लिए क्षेत्रीय बस स्टेशनों पर एलईडी डिस्प्ले यूनिट्स लगाना।

2013 से महिला सुरक्षा से संबंधित योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को निर्भया फंड दिया जाता है।

अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक चरण में 5,000 यूपीएसआरटीसी बसों को वीएलटीडी से लैस करने के लिए पहचान की गई है। और इन्हें लखनऊ में एक मुख्य कमांड सेंटर के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और 20 ऐसे क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

चौधरी ने कहा, ₹5,000 बसों में से, 1,000 से ज्यादा में अब तक उपकरण लगाए जा चुके हैं। गाजियाबाद का क्षेत्रीय केंद्र कौशांबी में बन सकता है। संभावना है कि दिसंबर के आखिर या जनवरी तक इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा।

नौकरी देने से पहले ई-बस चालक की हो सटीक स्वास्थ्य जांच, डीटीसी ने बस चलाने वाली निजी कंपनियों को लिखा पत्र

इलेक्ट्रिक बसों से होने वाले हादसों को देखते हुए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने सख्त कदम उठाया है। डीटीसी ने ई-बस चलाने वाली निजी कंपनियों को मेडिकल बोर्ड गठित करने की हिदायत दी है।

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक बसों से होने वाले हादसों को देखते हुए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने सख्त कदम उठाया है। डीटीसी ने ई-बस चलाने वाली निजी कंपनियों को मेडिकल बोर्ड गठित करने की हिदायत दी है। बोर्ड से चालकों के स्वास्थ्य की सटीक जांच कराने को कहा है। इससे फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही संबंधित चालक को सेवा में रखा जाएगा। इस बारे में डीटीसी ने संबंधित कंपनियों को पत्र लिखा है।

दरअसल, दिल्ली परिवहन निगम में चालकों व परिचालकों की भर्ती में स्वास्थ्य जांच पर जोर रहता है। इसके लिए निगम का अपना मेडिकल बोर्ड भी है। लेकिन जिन सेवा शर्तों पर निजी कंपनियां दिल्ली में ई-बस चला रही हैं, उसमें ई-बस का कंडक्टर तो डीटीसी का होता है, लेकिन चालकों की नियुक्ति वही कंपनी करती है, जिसके पास बस चलाने का जिम्मा है। कंपनियां अपने हिसाब से चालकों की भर्ती करती है। डीटीसी को शिकायतें मिली हैं कि बगैर उचित जांच के चालकों की भर्ती की गई है। डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के महासचिव मनोज शर्मा ने बताते हैं कि डीटीसी में चालक की नियुक्ति के लिए मेडिकल बोर्ड बना है। बोर्ड अगर फेल कर देता है तो चालक को नौकरी नहीं मिल सकती। जबकि निजी कंपनियों में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। ऐसी घटनाओं से डीटीसी की छवि धूमिल हो रही है। निजी कंपनियों के चालकों पर किमी पूरे करने का दबाव भी है। ऐसे में डीटीसी का मेडिकल बोर्ड गठन करने का निजी कंपनियों को भेजा गया प्रस्ताव कारगर हो सकता है।

बेड़े में जल्द शामिल होंगी 50 इलेक्ट्रिक बसें

इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में जल्द 50 और बसें शामिल होंगी। अधिकारियों के अनुसार, नवंबर अंत या फिर दिसंबर तक बसों के शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले अभी तक राजधानी की सड़कों पर 600 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। जबकि अगले साल मार्च के आखिर तक इनकी संख्या 1500 तक होनी है।

हाल में हुए हादसे

19 नवंबर को रोहिणी इलाके में एक इलेक्ट्रिक बस पलट गई, हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ।

चार नवंबर को रोहिणी सेक्टर तीन में इलेक्ट्रिक बस बेकाबू होकर कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया।

रैपिड ट्रेन प्रोजेक्ट के 415 करोड़ न देने पर दिल्ली सरकार को 'सुप्रीम' फटकार, SC ने कहा- अदालत को हल्के में न लें

परिवहन विशेष न्यूज

रैपिड ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए पैसा न दिये जाने पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यही एक रास्ता रह गया है कि आप सुनें। आप ये नहीं कह सकते कि दो महीने नहीं तीन महीने लगेंगे। आप इस अदालत को हल्के में नहीं ले सकते। बता दें कि दिल्ली सरकार को प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ रुपये का भुगतान करना है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम (RRTS) प्रोजेक्ट के लिए पैसा न दिये जाने पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट को दिये वचन की अवहेलना कर रहे हैं। एक सप्ताह का समय है, परियोजना का पैसा दे। अगर आप नहीं करेंगे तो कोर्ट विज्ञापन के बजट को इसमें ट्रांसफर कर देगा।

दिल्ली सरकार को देने हैं 415 करोड़ रुपये

इस प्रोजेक्ट में दिल्ली सरकार को 415 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। ये आदेश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने दिल्ली में प्रदूषण पर चल रही सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा आरआरटीएस परियोजना के लिए अपने हिस्से का पैसा न दिए जाने का मामला उठने पर दिये। आरआरटीएस परियोजना में दिल्ली को उत्तर प्रदेश के मेरठ, राजस्थान के अलवर और हरियाणा के पानीपत से जोड़ने वाला सेमी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर शामिल है।

पिछली सुनाई पर कोर्ट ने दिया था यह आदेश

24 जुलाई को आरआरटीएस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि वह अपने हिस्से का धन 415 करोड़ रुपये का भुगतान करे। उस समय कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा विज्ञापन पर खर्च किया गया तीन साल का लेखाजोखा मंगाकर देखा था, जिसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने तीन साल में विज्ञापन पर करीब 1100 करोड़ रुपये खर्च किये थे।

उस समय भी कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा था कि अगर दिल्ली सरकार पिछले तीन साल में विज्ञापन पर 1100 करोड़ खर्च कर सकती है तो निश्चित तौर पर इन्फ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट पर भी खर्च कर सकती है। दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट को परियोजना के लिए पैसे का भुगतान करने का भरोसा दिलाया गया था। मंगलवार को दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें इस मामले में जवाब दाखिल करना है, लेकिन पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा क्या जवाब देंगे।

दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा

आपने कोर्ट को दिए गए वचन का पालन नहीं किया है। पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस कौल ने कहा कि हमने 24 जुलाई को आपसे कहा था कि हम आपका विज्ञापन का बजट ले लेंगे। अब हम विज्ञापन का बजट रोकने जा रहे हैं। पीठ ने कहा कि वैसे तो बजट प्रबंधन सरकार के देखने की चीज है लेकिन जब ऐसी राष्ट्रीय महत्व की परियोजना प्रभावित होती है और पैसा विज्ञापन पर खर्च होता है तो कोर्ट उस पैसे को इस परियोजना के मद में ट्रांसफर करने का आदेश देने का इच्छुक है।

राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है- कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है, इससे प्रदूषण पर भी असर पड़ेगा। इसके बाद कोर्ट ने आदेश में लिखाया कि विज्ञापन के उद्देश्य से रखा गया फंड इस परियोजना में ट्रांसफर किया जाए, लेकिन तभी दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से ऐसा आदेश न देने का अनुरोध किया और कहा कि उन्हें निर्देश लेने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। वकील के अनुरोध पर कोर्ट ने अपने आदेश को एक सप्ताह के लिए टाल दिया।

अदालत को हल्के में नहीं ले सकते- सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि अगर एक सप्ताह के भीतर दिल्ली सरकार पैसे का भुगतान नहीं करती है तो विज्ञापन के बजट को इस परियोजना में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कोर्ट ने मामले को 28 नवंबर को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया। मौखिक टिप्पणी में जस्टिस कौल ने कहा कि यही एक रास्ता रह गया है कि आप सुनें। आप ये नहीं कह सकते कि दो महीने नहीं तीन महीने लगेंगे। आप इस अदालत को हल्के में नहीं ले सकते।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

प्रेग्नेंसी में घातक है थायराइड का बढ़ना, बच्चे को हो सकता नुकसान, डॉक्टर से जानें लक्षण और बचाव के उपाय

गर्भावस्था में होने वाले हार्मोनल बदलावों के कारण कई महिलाओं को थायरॉयड की समस्या हो जाती है. प्रेग्नेंसी के दौरान यह थायरॉयड पेट में पल रहे शिशु की सेहत के लिए ठीक नहीं है. अब सवाल है कि प्रेग्नेंसी में थायरॉयड कैसे नुकसानदायक? क्या हैं लक्षण? कैसे करें बचाव? इन सवालों के बारे में विस्तार बता रही हैं डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज दिल्ली की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. ज्योति यादव'

प्रेग्नेंसी का समय महिलाओं के लिए जितना सुखद भरा होता है, उतना ही कठिनाई भरा भी होता है. क्योंकि गर्भावस्था के समय महिलाओं के शरीर में तेजी से बदलाव होता है, जिससे कई तरह की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इन्हीं में से एक है थायरॉयड की परेशानी. जी हां, गर्भावस्था में होने वाले हार्मोनल बदलावों के कारण कई महिलाओं को थायरॉयड की समस्या हो जाती है. प्रेग्नेंसी के दौरान यह थायरॉयड पेट में पल रहे शिशु की सेहत के लिए ठीक नहीं है. बता दें कि, थायरॉयड हमारे गले में मौजूद तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है. यह थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, जो शरीर में एनर्जी और मेटाबॉलिज्म के स्तर को कंट्रोल करता है. जब इस ग्रंथि में गड़बड़ी आने लगती है, तो थायरॉयड रोग हो जाता है. अब सवाल है कि प्रेग्नेंसी में थायरॉयड कैसे नुकसानदायक? क्या हैं लक्षण? कैसे करें बचाव? इन सवालों के बारे में विस्तार बता रही हैं डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज दिल्ली की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. ज्योति यादव'

प्रेग्नेंसी में थायरॉयड क्यों नुकसानदायक?

थायरॉयड की ज्यादा मात्रा गर्भवती महिला और उसके शिशु की सेहत के लिए खराब मानी जाती है. हाइपरथायरॉयडिज्म के कुछ मामलों में महिला को उल्टियां आना या फिर जी मिचलाना जैसी दिक्कतें आ सकती हैं. थायरॉयड के कारण बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है, बच्चा असमान्य भी हो सकता है.

बॉडी को एक्टिव बनाएं रखें और डॉक्टर की सलाह पर योग और हल्के वर्कआउट की आदत डालें. इसके अलावा, थायरॉयड पीड़ित प्रेग्नेंट महिलाओं के बच्चों को यानी नवजात शिशुओं का नियोनेटल हाइपोथायरॉयड की समस्या हो सकती हैं.

प्रेग्नेंसी में थायरॉयड बढ़ने के लक्षण

प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को दो तरह के थायरॉयड की समस्या हो सकती है. पहला हाइपोथायरॉयडिज्म, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि थायरॉयड ग्रंथि जरूरत से कम थायरॉयड हार्मोन का उत्पादन कर रही है. इस समस्या में वजन बढ़ाना, अत्यधिक थकान, कब्ज, ज्यादा ठंड लगना, मांसपेशियों में ऐंठन और ध्यान लगाने में दिक्कत आदि लक्षण देखने को मिलते हैं.

प्रेग्नेंसी में थायरॉयड कंट्रोल करने के उपाय

गर्भावस्था में थायरॉयड को कंट्रोल रखने के लिए अपने खानपान का विशेष ध्यान रखें. साथ ही नियमित रूप से व्यायाम और योग करने से थायरॉयड को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. थायरॉयड को कंट्रोल रखने के लिए नियमित रूप से दावा का सेवन करें. प्रेग्नेंसी में थायरॉयड लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए आपको तनाव लेने से बचें, जंक फूड और शुगर युक्त चीजों का ज्यादा सेवन ना करें. इसके अलावा, समय-समय पर डॉक्टर से अपना चेकअप कराएं.

गर्भावस्था में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना बेहद खतरनाक, 5 लक्षणों से करें बीमारी की पहचान, डॉक्टर से समझें बचाव के तरीके

प्रेग्नेंसी के दौरान अच्छी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल जरूरी है. प्रेग्नेंसी के दौरान अच्छी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल जरूरी है.

प्रेग्नेंसी के दौरान अच्छी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल बेहद जरूरी है. कई बार कुछ गलत खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है. अब सवाल है कि प्रेग्नेंसी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है? क्या हैं इसके जोखिम? कैसे करें लक्षणों की पहचान और क्या हैं बचाव के तरीके? इन सवालों के बारे में बता रही हैं डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज दिल्ली की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. ज्योति यादव...

प्रेग्नेंसी का समय महिलाओं के लिए जितना सुखद भरा होता है, उतना ही कठिनाई भरा भी होता है. क्योंकि गर्भावस्था के समय महिलाओं के शरीर में तेजी से बदलाव होता है. ऐसे में खुद की ठीक से देखभाल बेहद जरूरी है. इस दौरान दो चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है- पहली अच्छी डाइट और दूसरी हेल्दी लाइफस्टाइल. क्योंकि आपका खानपान आपकी और आपके बच्चे की सेहत पर सीधा असर डालती है. कई बार कुछ गलत खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है. दरअसल, प्रेग्नेंसी में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना महिलाओं के लिए घातक हो सकता है. ऐसे में जरूरी है कि लक्षणों को पहचानकर समय पर डॉक्टर की सलाह लें. अब सवाल है कि प्रेग्नेंसी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है? क्या हैं इसके जोखिम? कैसे करें लक्षणों की पहचान और क्या हैं बचाव के तरीके? इन सभी सवालों के बारे में बता रही हैं डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज दिल्ली की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. ज्योति यादव'

प्रेग्नेंसी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण?

एक्सपर्ट के मुताबिक, ज्यादातर महिलाओं में प्रेग्नेंसी के समय कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायत रहती है. इस परेशानी की मुख्य वजह महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव का होना हैं. इसी के चलते उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है. दरअसल, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में एक मोम की तरह दिखने वाला चिपचिपा तरल पदार्थ है. शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कई तरह की समस्याएं जन्म दे सकती हैं, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का भी खतरा शामिल हैं. हालांकि हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छा खानपान इस परेशानी से बचाने में आपकी मदद कर सकता है.

प्रेग्नेंसी में हाई कोलेस्ट्रॉल के जोखिम

गर्भावस्था में लगातार कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना खतरनाक हो सकता है. ऐसे में इसकी पहचान कर तुरंत एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए. बता दें कि, गर्भास्था में यदि शरीर में कोलेस्ट्रॉल फी बढ़ जाए, तो इससे कई तरह की समस्याएं होने का खतरा बढ़ता है, जिसमें- हाई ब्लड प्रेशर, प्रीमैच्योर डिलीवरी, बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर, हार्ट अटैक जैसी परेशानियां शामिल हैं.

हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण?

डॉक्टर के मुताबिक, प्रेग्नेंसी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर छाती या सीने में तेज दर्द महसूस होना, उल्टी और मतली महसूस होना, हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी ज्यादा होना, सांस लेने में दिक्कत होना और बॉडी में थकान या कमजोरी महसूस होने जैसे शुरुआती लक्षण हैं. इन लक्षणों की पहचान कर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर ऑप्शन है.

कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए इन चीजों से रखें दूरी?

गर्भावस्था में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कोई भी कारण हो, लेकिन डॉक्टर इस दौरान किसी भी तरह की दवा का सेवन करने की सलाह नहीं देते हैं. दरअसल, प्रेग्नेंसी के दौरान दवा का सेवन करने से पेट में पल रहे बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है. इसके लिए बेहतर है कि नियमित एक्सरसाइज करें, अच्छी नींद लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं, साबुत अनाज खाएं, फल-सब्जियों का सेवन करें और धूम्रपान-शराब से दूरी रखें.

वक्त पर पकड़ना है काला मोतिया तो एक बार करें ये काम, पॉल्यूशन का जंजाल होगा खत्म

पॉल्यूशन के कारण लोगों को आंखों में जलन, एलर्जी और गले में खराश जैसी परेशानियां हो रही हैं। इससे बचने के लिए विशेष टिप्स दिए गए हैं। आंखों की जांच और डाइलेट करने से आंखों की परेशानियों को समझना आसान होता है। मोबाइल का अधिक इस्तेमाल मायोपिया को बढ़ावा देता है।

पॉल्यूशन ने अपना जोर लगाया हुआ है। लोगों को इस वजह से आंखों में जलन, सांसों की परेशानी, एलर्जी की शिकायत, गले में खराश समेत तमाम तरह की परेशानियों ने घेर रखा है। साथ ही मौसम बदल रहा है और त्योहारों का सीजन भी चल रहा है।

ऐसे में इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं सेहतमंद बने रहने के लिए बेस्ट टिप्स। इन्हें अपनाकर आप खुद को अच्छी सेहत का तोहफा दे सकते हैं।

1. साल में एक बार आई चेकअप

साल में एक बार आंखों की जांच होनी चाहिए, वह भी आंखों को डाइलेट करके। आजकल कंप्यूटर के माध्यम से टेस्टिंग होती है। लेकिन आंखों की अंदरूनी परेशानी का पता लगाने के लिए डाइलेट करने के खास लिक्विड (Tropicamide, Phenylephrine Hydrochloride) की चंद बूंदें आंखों में डाली जाती हैं।

इससे डॉक्टर को आंखों के भीतरी हिस्से, नसें आदि अच्छी तरह दिख जाती हैं। इससे आंखों की परेशानियों को समझना आसान हो जाता है। इस जांच का चलन ज्यादातर शुगर पेशेंट्स और उम्र से जुड़ी परेशानियों में होता है।

फिर भी इस तरह की जांच सभी के लिए होनी चाहिए। 40 साल की उम्र के बाद हर साल आंखों का प्रेशर जरूर चेक कराएं। इससे काला मोतिया वक्त पर पकड़ में आ जाता है।

2. मोबाइल से दूरी

मोबाइल की जरूरत सभी को है। काफी संख्या में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग ऐसे हैं, जिनकी यह जरूरत लत बन गई है। लेकिन 6 से 13 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल बड़ी परेशानी पैदा कर रहा है। इससे मायोपिया हो रहा है।

इसमें दूर की निगाह कमजोर हो जाती है। किसी शख्स को 6 फुट की दूरी पर मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट साफ दिखाई न दे तो इसका मतलब है कि वह मायोपिया का शिकार हो सकता है।

ज्यादातर बच्चे मायोपिया वाले ही होते हैं। आम रुटीन में हम एक मिनट में 20 से 25 बार पलकों को झपकाते हैं, लेकिन स्क्रीन देखते समय यह महज 5 से 7 बार रह जाती है।

3. 20:20:20 फॉर्मूला

अगर कोई शख्स किसी से बात कर रहा हो, कहीं जा रहा हो तो वह स्वाभाविक तौर पर कभी नजदीक तो कभी दूर देखता रहता है। लगातार नजदीक देखने का मसला नहीं बनता। लेकिन जब कोई शख्स लगातार मोबाइल या लैपटॉप आदि की स्क्रीन को देखता रहता है तो 'दूरदर्शन' की जरूरत होती है। इसलिए ऐसे शख्स को 20:20:20 फॉर्मूले पर अमल करना जरूरी है यानी हर 20 मिनट बाद 20 बार पलकें झपकना, फिर लगातार 20 सेकंड तक 20 फुट या इससे दूर देखना चाहिए।

इससे आंखों को आराम मिलता है। साथ ही ड्राइ आंखों की परेशानी भी कम होती है। इसके अलावा स्क्रीन पर काम करते हुए बार-बार पलकें झपकाएं। याद रखें, हर 5 सेकंड में एक बार पलकें झपकनी चाहिए।

महिलाओं के लिए पीली किशमिश अधिक फायदेमंद या काली किशमिश? एक्सपर्ट ने कंफ्यूजन को किया दूर, बताए 5 चमत्कारी लाभ

काली किशमिश महिलाओं के लिए अधिक फायदेमंद होती है. यह न सिर्फ प्रेग्नेंसी बल्कि यौन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भी असरदार मानी जाती है. यह इतनी कारगर है कि इसका पानी भी सेहत के लिए चमत्कार की तरह काम कर सकता है. आइए गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. ज्योति यादव से जानते हैं काली किशमिश के चमत्कारी लाभ-

किशमिश सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है. खासतौर पर महिलाओं के लिए. यदि आप किशमिश को भिगोकर खाते हैं तो इसका आपको दोगुना लाभ प्राप्त हो सकता है. हालांकि, इसका लाभ लेने के लिए महिलाएं अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज में आती हैं कि उन्हें पीली किशमिश खाना चाहिए या काली किशमिश. जी हां, एक्सपर्ट के मुताबिक, काली किशमिश महिलाओं के लिए अधिक फायदेमंद होती है. यह न सिर्फ प्रेग्नेंसी बल्कि यौन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भी असरदार मानी जाती है. यह इतनी कारगर है कि इसका पानी भी सेहत के लिए चमत्कार की तरह काम कर सकता है. आइए डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज दिल्ली की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. ज्योति यादव से जानते हैं काली किशमिश के चमत्कारी लाभ-

महिलाओं के लिए काली किशमिश के 5 चमत्कारी लाभ

यौन स्वास्थ्य बेहतर बनाए: एक्सपर्ट के मुताबिक, महिलाओं के लिए काली किशमिश अधिक फायदेमंद होती है. बता दें कि, काली किशमिश में अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में होता है, जो यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है. दरअसल, अमीनो एसिड संभावित रूप से गर्भधारण की संभावना को भी बढ़ा सकता है. इनमें एल-आर्जिनिन की मौजूदगी गर्भाशय और अंडाशय में ब्लड फ्लो को बढ़ा सकती है.

यौन स्वास्थ्य बेहतर बनाए: एक्सपर्ट के मुताबिक, महिलाओं के लिए काली किशमिश अधिक फायदेमंद होती है. बता दें कि, काली किशमिश में अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में होता है, जो यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है.

प्रजनन क्षमता बढ़ाए: महिलाओं को काली किशमिश अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए. दरअसल, प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए काली किशमिश का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है. इसके लिए इसे रातभर भीगने दें और अगले दिन छान लें. इसके बाद किशमिश को पीसकर उसका रस निकाल लीजिए. फिर आप इस मिश्रण को पी सकते हैं.

प्रेग्नेंसी में करें सेवन: काली किशमिश को गर्भावस्था के दौरान अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए. गर्भावस्था के दौरान काली किशमिश को पानी में भिगोने से कब्ज से प्रभावी रूप से राहत मिल सकती है. इसके अलावा काली किशमिश के पानी को डाइट में शामिल करने से गर्भवती महिलाओं को कई लाभ मिल सकते हैं. इसके अलावा, इसका नियमित सेवन एनीमिया को रोकने और हीमोग्लोबिन लेवल को बनाए रखने में मदद कर सकता है.

स्किन के लिए फायदेमंद: विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से युक्त काली किशमिश स्किन को पोषण देने का काम करती है. बता दें कि, इसके डिटॉक्सिफाइंग और एंटी-एजिंग गुण त्वचा को साफ, चमकदार और लंबे समय तक जवां बनाए रखने में मदद करते हैं. इसके अलावा, विटामिन सी मुंहासे को रोकने में भी मदद करता है. इसका लाभ लेने के लिए रोज एक कप पानी में 8-10 काली किशमिश भिगोकर इसका पानी खाली पेट पीना चाहिए.

इम्यूनिटी मजबूत करें: गर्भावस्था के दौरान इम्यून सिस्टम में बदलाव आते हैं. कई विटामिन और मिनरल से भरपूर काली किशमिश का पानी, इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकता है, जो सामान्य बीमारियों और इंफेक्शन से सुरक्षा प्रदान करता है. वहीं, काली किशमिश के पानी में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर लेवल को स्थिर बनाए रखने में योगदान देता है, जिससे इन कॉम्प्लीकेशन्स की संभावना कम हो जाती है.

इस सीजन देशभर में होंगी 38 लाख से ज्यादा शादियां

बरातियों संग झूमेगा बाजार; 4.74 लाख करोड़ के कारोबार का अनुमान

परिवहन विशेष न्यूज

इस मौसम में देशभर में 38 लाख से अधिक शादियों तथा बाजार में 4.74 लाख करोड़ रुपये के आने का अनुमान है। पिछले साल इस अवधि में करीब 32 लाख शादियां हुई थी जिससे बाजार को 3.75 लाख करोड़ रुपये का व्यापार मिला था। इस सीजन के दौरान लगभग सात लाख शादियों में औसत तीन लाख खर्च होगा।

नई दिल्ली। शादियों के मौसम में बरातियों संग देशभर के बाजार भी झूमेंगे। देव उठनी एकादशी 23 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक के इस मौसम में देशभर में 38 लाख से अधिक शादियों तथा बाजार में 4.74 लाख करोड़ रुपये के आने का अनुमान है। पिछले साल इस अवधि में करीब 32 लाख शादियां हुई थी, जिससे बाजार को 3.75 लाख करोड़ रुपये का व्यापार मिला था।

दिल्ली में इस दौरान चार लाख से अधिक जोड़ों के दाम्पत्य जीवन में बंधने तथा यहां के बाजार में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये आने का अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे, शादियों की खरीदारी दीपावली से ही जारी है। मुख्य तौर पर चांदनी चौक, करोलबाग, खारी बावली व सदर बाजार की चमक शादियों के मौसम में भी बरकरार रहने की उम्मीद है।

कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने देश के प्रमुख 30 व्यापारिक शहरी केंद्रों में वस्तुओं व सेवाओं के हितधारकों से विस्तृत चर्चा के बाद इस सीजन में 38 लाख से अधिक शादियों का अनुमान जताया है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल के अनुसार शादी की खरीदारी और विभिन्न सेवाओं के जरिए देशभर के बाजारों लगभग 4.74 लाख करोड़ रुपये का भारी प्रवाह होगा।

50 हजार शादियों का औसत खर्च एक करोड़ से अधिक

इस सीजन के दौरान लगभग सात लाख शादियों में औसत तीन लाख खर्च होगा। इसी तरह आठ लाख शादियों में प्रत्येक पर छह लाख रुपये से अधिक तथा 10 लाख शादियों में 10-10 लाख खर्च का अनुमान है। वहीं, सात लाख शादियों में 15-15 लाख रुपये का खर्च होगा। इसी तरह पांच लाख विवाह में प्रत्येक पर 25 लाख रुपये का खर्च, जबकि 50 हजार शादियों में खर्च प्रत्येक पर 50 लाख रुपये होगा। वहीं, 50 हजार शादियां ऐसी होंगी जिसमें एक करोड़ रुपये या उससे अधिक खर्च होगा। कुल खर्च में 50 प्रतिशत खर्च शादी-ब्याह पर तथा वस्तुओं की खरीद-फरोख्त व सेवाओं पर 50 प्रतिशत खर्च होता है।

इसपर होगा खर्च

साड़ी, लहंगा और परिधान पर 10 प्रतिशत

आभूषण पर 15 प्रतिशत

इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर 5 प्रतिशत

सूखे मेवे, फल, मिठाई और नमकीन पर 5 प्रतिशत

खाद्यान्न, किराना और सब्जियों पर 5 प्रतिशत

उपहार वस्तुओं में 4 प्रतिशत और शेष 6 प्रतिशत अन्य विविध वस्तुओं पर। इसी तरह टेंट, आयोजन स्थल, यात्रा, बैंड समेत अन्य पर भी खर्च होंगे।

ये है शादियों का शुभ दिन

चांदनी चौक स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित रमेश चंद शर्मा के अनुसार देव उठनी एकादशी 23 नवंबर से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। इस माह 23, 24, 27, 28 व 29 शादियों के लिए शुभ दिन है, जबकि दिसंबर में 3,4,6,7,8, 9 और 15 की तिथि विवाह का शुभ मुहुर्त है। उसके बाद, जनवरी के मध्य 16 जनवरी से शादियों का मुहुर्त आएगा। उनके अनुसार देव उठनी पर ही दिल्ली में 25 हजार से अधिक शादी होगी।

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष शादियों के मौसम में 25 प्रतिशत से अधिक बिक्री में बढ़ोत्तरी का अनुमान है। खासकर लहंगा चुनरी, साड़ी, गर्म सूट, शेरवानी, कोट-पैंट समेत अन्य की मांग खूब है। यह इसलिए क्योंकि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष शादियों की तिथियां अधिक हैं। **-श्रीभगवान बंसल, महासचिव, दिल्ली हिंदुस्तानी**

दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कब होगा सुधार?

नई दिल्ली। प्रदूषण का संकट झेल रहे दिल्लीवालों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली में प्रदूषण स्तर में सुधार देखा जा सकता है। दिल्ली में प्रदूषण से दो दिन मामूली राहत देखने को मिली थी।

दो दिन बाद सोमवार को फिर बढ़ा प्रदूषण

हालांकि, दो दिन की मामूली राहत के बाद सोमवार को एक बार फिर से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली। दिल्ली के तीन इलाकों में फिर से गंभीर श्रेणी में हवा पहुंच गई थी। सोमवार को पंजाबीबाग, जहांगीरपुरी और बवाना का सूचकांक (AQI) 400 के ऊपर दर्ज किया।

पर्यावरण मंत्री ने दी राहत की खबर

इस बीच प्रदूषण के चलते जहरीली हवा में सांस ले रहे दिल्ली के लोगों के लिए राहतभरी खबर है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा जा सकता है। आने वाले दिनों में हवा में और सुधार देखने को मिलेगा। गोपाल राय ने आगे कहा कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक, हवा के गंभीर श्रेणी में जाने की संभावना नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार हर चीज पर नजर रख रही है। पंजाब सरकार ने पिछले साल की तुलना में 50 फीसद से पराली जलाने पर काबू पाया है।

ग्रेप-4 के तहत प्रतिबंध हटाए गए

ध्यान देने वाली बात है कि वायु गुणवत्ता में सुधार होने और अति गंभीर श्रेणी से बाहर आने के चलते दिल्लीवालों के ऊपर लगाए गए ग्रेप-4 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) चरण के प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। अब ग्रेप-4 के तहत लागू सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे, जिसमें निर्माण कार्य से लेकर वाहनों का प्रतिबंध भी शामिल है।

पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बीएमसी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन

स्वतंत्र सिंह भुल्लर, नई दिल्ली। टी- 21 अतुल ग्रोव रोड पर 22 /11/2023 को होने जा रही पुरानी पेंशन बहाली महारैली को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, प्रेस में सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के महामत्री ने अपनी बात रखी।

जिसमें 1.पुरानी पेंशन की बहाली के लिए भारतीय मजदूर संघ सड़क पर 2. केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर जंतर मंतर पर, विषय पर चर्चा की गई। NPS को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम (CCS Pension Rule-72) लागू करने के सम्बन्ध में भारतीय मजदूर संघ से सम्बन्ध ₹ सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ ₹ के अखिल भारतीय आवाहन पर सरकारी कर्मचारिओं का प्रतिनिधित्व कर रहे महासंघों और उनसे सम्बन्ध संगठन कल 22 नवम्बर 2023 को संसद भवन पर पूरे देश के सरकारी कर्मचारी एक विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ और उससे सम्बन्ध महासंघ प्रारम्भ से ही NPS का विरोध करते आ रहे हैं एवम अब तक कई देश व्यापी आंदोलन हो चुके हैं। UPA के 10 साल के कार्य काल में NPS में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ लेकिन हमारी मांग पर NDA सरकार ने NPS मे निश्चित रूप से कुछ सुधार किये हैं जैसे वर्ष 2016 मे ग्रेजुटी प्रदान की, फैमिली पेंशन CCS पेंशन रूल-1972 के अंतर्गत विकल्प चुनने की सुविधा दी गई, नियोक्ता का अंश 10% से बढ़ा कर 14% किया आदि। इन सुधारों के बाद भी कर्मचारियों का असन्तोष दूर नही हुआ क्योंकि NPS एक गारन्टी कृत पेंशन स्कीम नही है। अनेक राज्यों मे कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के नाते अच्छी सर्विस छोड़ कर इस OPS के नाते सरकारी विभागों मे जॉइन करते हैं।

साधू सिंह ने बताआ विगत कुछ वर्षों मे कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को पुनः पुरानी पेंशन स्कीम (CCS PENSION RULE-1972) को लागू कर NPS को समाप्त किया है। इस से शेष प्रदेशों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों मे यह उम्मीद जागृत हुई कि हमारे बारे मे सरकार कुछ सोचेगी परंतु अभी तक कोई घोषणा ना होने से कर्मचारियों मे निराशा एवम असंतोष व्याप्त है। पहले केंद्र सरकार के आदेशों को लागू कराने के लिए राज्य कर्मचारी आंदोलन करते थे किंतु आज केंद्र सरकार के कर्मचारी राज्यों मे लागू व्यवस्था OPS की मांग कर रहे हैं।

बी एम एस मांग करता हैं कि सरकार पुरानी पेंशन अर्थात 50% गारन्टी कृत पेंशन लागू करे। इस प्रदर्शन मे पूरे देश से पॉस्टल, रेलवे, डिफेंस, जी इस आई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ई इस आई, ई पी एफ ओ आदि के अलावा राज्य कर्मचारी एवम स्वायत शासी विभाग भाग लेंगे। ऐसा ना होने पर आंदोलन का अगला चरण निश्चित रूप से शुरु किया जायेगा।

प्रेस वार्ता में मुकेश सिंह महामंत्री डिफेंस फेडरेशन, दिनेश सिंह अध्यक्ष डिफेंस फेडरेशन, वीरेन्द्र शर्मा उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, अनंत पाल महामंत्री पोस्टल फेडरेशन, एस. के. सिंह संगठन मंत्री, डॉ दीपेंद्र चाहर महामंत्री भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश उपस्थित रहे।

छठ पूजा पर बिहार जाने के लिए पत्नी ने किया झगड़ा, नाराज पति ने तीसरी मंजिल से कूदकर दी जान

फरीदाबाद में एक शख्स ने पत्नी से झगड़ा के बाद तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। जानकारी के मुताबिक उसकी पत्नी छठ पूजा के लिए बिहार जाना चाहती थी। इसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। वहीं कहा जा रहा है कि घटना के दिन गली में उसकी पत्नी किसी अन्य युवक से बात कर रही थी। इसके बाद वह यह फैसला लिया।

फरीदाबाद। जिले के एसजीएम नगर राजा चौक के पास तीन मंजिला मकान की छत से एक युवक कूद गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक का नाम सूरज है। उसकी करीब डेढ़ साल पहले लव मैरिज हुई थी। इनकी एक दो महीने की बेटी भी है। युवक के माता-पिता अलग रहते हैं।

सूरज शनिवार दोपहर को अपने माता-पिता के घर आया था। उस दौरान माता-पिता घर पर नहीं थे। दोनों आगरा किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे। आसपास के लोगों ने बताया कि गली में युवक के पास दो महिलाएं खड़ी थी। अनुमान है कि उस दौरान सूरज की पत्नी भी थी।

इस दौरान वह मकान की तीसरी मंजिल की छत पर चढ़ गया और कूद गया। एसजीएम नगर थाने से एसआई पंकज ने बताया कि इस मामले में अभी किसी ने कोई शिकायत नहीं दी है। मामले की जांच की जा रही है। शव का रविवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

पति-पत्नी में हुई थी कहासुनी

जानकारी के मुताबिक सूरज की पत्नी छठ पूजा के लिए अपने गांव जाना चाहती थी। उसने पति से गांव छोड़ने के लिए कहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। यह बात सूरज की पत्नी ने अपनी मां को भी बताई थी।

शादी के आठ साल बाद भी नहीं थी कोई संतान, रोज-रोज के झगड़े इतने बढ़े; दंपती ने उठा लिया खौफनाक कदम

फरीदाबाद। जिले के डबुआ थाना अंतर्गत नवादा गांव में शुक्रवार देर रात दंपती ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक, दंपती के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव था। रात को भी किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नवादा गांव में रहने वाला अरुण ग्रेटर फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल की कैंटीन में काम करता था। उसकी शादी 2015 में सोहना के हरचंदपुर गांव के पास इशाका की रहने वाली शीतल से हुई थी। करीब सालभर पहले इनकी बेटी की जन्म के साथ ही मौत हो गई थी। फिलहाल और कोई संतान नहीं थी।

4 मंजिली मकान, 50 वर्ग मीटर में अब नहीं बन सकेगें

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

राजधानी दिल्ली में 50 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर अब 4 मंजिला फ्लोर नहीं बनाया जा सकेगा।ऐसा इसलिए कि दिल्ली रियल इंस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (दिल्ली रेरा) ने हर फ्लोर पर आवासीय यूनिट की संख्या कम कर दी है। यानि 50 वर्ग मीटर तक के प्लॉट साइज पर 3 अवासीय यूनिट ही बनाई जा सकती है।प्रत्येक फ्लोर पर आवासीय यूनिट एक ही होगी।

इस बावत रेरा ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें 50 वर्ग मीटर से लेकर 3750 या इससे बडे आकार पर आवासीय यूनिट बनाने की सीमा तय की है। नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के मार्च, 2008 के एक आदेश का हवाला भी दिया गया है। और उसी आर्डर के अनुसार अलग-अलग साइज के प्लॉटो पर आवासीय यूनिट बनाने की सीमा तय करने की बात कही गई है। इस बारे में दिल्ली रेरा ने दिल्ली कैंट बोर्ड, एमसीडी और डीडीए को भी पत्र लिखा है। और नोटिफिकेशन के अनुसार ही बिल्डिंग प्लॉन जारी करने के लिए कहा है। साथ सी सब- रजिस्ट्रार को भी रेरा ने पत्र लिखा है, और 15 सितंबर के बाद किसी प्रोपर्टी का रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन के अनुसार आवासीय इकाईयों को चेक कर ही किया जाए।

इस बावत भारतीय जनता पार्टी ने इस नोटिफिकेशन पर अपना विरोध जताया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि यह अधिसूचना रियल एस्टेट कारोबार को नष्ट कर देगी। इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। जबकि दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि रेरा केन्द्र सरकार के तहत आता है। लिहाजा बीजेपी को दिल्ली सरकार के बजाय केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहिए। उन्हें पब्लिक को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए।

वोटों की राजनीति के चलते गैस चैंबर बन गए हैं दिल्ली व एनसीआर

योगेंद्र योगी

हर दिन हजारों की संख्या में श्वांस के रोगियों की तादाद बढ़ रही है। बच्चों और बुजुर्गों का जीना मुहाल हो चुका है। दिल्ली का वायुमंडल विश्व में सबसे प्रदूषित करार दिया जा चुका है। वोटों की राजनीति राजधानी के लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है।

जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने करीब 60 लाख यहूदियों की गैस चैम्बर में जहरीली गैस छोड़ कर हत्या की थी। कमोबेश यही हालत देश के नेता राजधानी दिल्ली के करोड़ों लोगों की कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हिटलर ने नस्लवादी मानसिकता से सुनयोजित तरीके से इस भीषण नरसंहार को अंजाम दिया था और भारत में नेताओं की वोटों की राजनीति के कारण इसे अंजाम दिया जा रहा है। प्रदूषित जहरीली हवा से तिल-तिल करके मरने के लिए करोड़ों लोगों को छोड़ दिया गया है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र के करोड़ों लोग जहरीली हवा लेने को मजबूर हैं। वायु प्रदूषण से मुंबई की हालत भी खराब है। दिल्ली की तरह मुंबई भी गैस चेंबर बनी हुई है। मुंबई की हवा में सांस लेना एक दिन में 100 सिगरेट पीने के बराबर आंकी गई है। दिल्ली की हालत इससे भी कई गुना ज्यादा खराब है। दिल्ली में इतनी बड़ी आबादी लापरवाही और राजनीतिक स्वार्थों के चलते भीषण प्रदूषित हवा से तिल-तिल करने को मजबूर है।

हर दिन हजारों की संख्या में श्वांस के रोगियों की तादाद बढ़ रही है। बच्चों और बुजुर्गों का जीना मुहाल हो चुका है। दिल्ली का वायुमंडल विश्व में सबसे प्रदूषित करार दिया जा चुका है। वोटों की राजनीति राजधानी के लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है। यदि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं देता तो दिल्ली और आस-पास के हालात शायद हिटलर के कत्लगाह बने जहरीले गैस चैम्बर जैसे बन जाते। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में जानलेवा बने वायु प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की दमघोंटू जहरीली हवा लोगों के स्वास्थ्य की हत्या के लिए जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण एक राजनीतिक लड़ाई नहीं बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर सर्दियों में दिल्ली के वायु प्रदूषण में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी के पीछे पड़ोसी राज्यों- पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना एक प्रमुख कारक है। इसमें पंजाब सरकार से पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील से कहा कि हम नहीं जानते कि आप इसे कैसे करते हैं, यह आपका काम है। लेकिन इसे रोका जाना चाहिए। तुरंत कुछ किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि पंजाब में खेतों में लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में गिरावट के लिए पराली जलाने का प्रमुख योगदान है। उन्होंने कहा कि सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) और राज्य कह रहे हैं कि वे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं। लेकिन पराली जलाना अभी भी जारी है। प्रदूषण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश को निर्देश देते हुए कहा कि ये राज्य पराली जलाना तुरंत बंद कर दें। मामले पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया।

जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने वाले स्मॉग टावर लगाए गए और उनका खूब प्रचार किया गया लेकिन वह बंद पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पराली को नष्ट कर खाद बनाने वाले केमिकल के प्रचार पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पराली को खाद बनाने वाले एक केमिकल का दावा किया था। क्या यह कभी सफल हुआ? लगता है यह सब सिर्फ दिखावा ही था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केवल एक दूसरे पर दोषारोपण का खेल जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अपना बुलडोजर शुरू किया तो हम नहीं रुकेंगे। अदालत ने यह भी पूछा कि पंजाब में धान क्यों उगाया जा रहा है, जबकि जलस्तर पहले से ही इतना नीचे है। आप क्या कर रहे हैं? अपने जलस्तर को देखें। आप पंजाब में धान की अनुमति क्यों दे रहे हैं? आप पंजाब को हरित भूमि से बिना फसल वाली भूमि में बदलना चाहते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि पंजाब में धान की खेती का विकल्प खोजा जाए। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं से राज्य की आबोहवा खराब हो रही है। इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ रहा है। प्रमुख शहर जैसे अमृतसर, बठिंडा, लुधियाना में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) काफी खराब कैटेगरी में चल रहा है। पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। पंजाब में कुल 1,830 मामले दर्ज किया जा चुके हैं। फिरोज़पुर दूसरे नंबर पर हैं। अकेले फिरोज़पुर में 299 मामले पराली जलाने के दर्ज किए गए है।

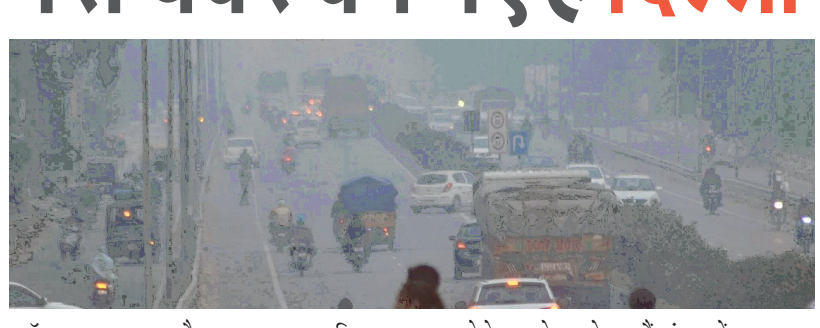

दिवाली के बाद वायु प्रदूषण की हालत और भी खराब हो गयी है। चिकित्सकों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो फेफड़ों के इंफेक्शन से ठीक होने के बाद भी सांस फूलने की शिकायत कर रहे हैं। युवा मरीजों में भी ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कई गंभीर मरीजों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है। ऐसे लक्षणों वाले सभी मरीजों में करीब 50 प्रतिशत या दो में से एक जो ओपीडी में आ रहे हैं, उन्हें कम से कम एक या दो दिनों के लिए भर्ती होना पड़ रहा है। करीब 30 प्रतिशत मरीजों को आईसीयू में एडमिट होने की जरूरत होती है। वायु प्रदूषण से लंग्स कैंसर के मामले भी बढ़ रहे हैं। द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, वायु प्रदूषण के कारण 2019 में भारत में 16.7 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। जो देश में अब तक हुई कोविड-19 से हुई मौतों से दस गुना अधिक है। जिससे लगभग 36.8 बिलियन डॉलर (2,71,446 करोड़ रुपये) का आर्थिक नुकसान हुआ। एम्स, आईसीएमआर और आईआईटी-दिल्ली के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी, 2019 शीर्षक से, इनडोर और आउटडोर दोनों में वायु प्रदूषण के आर्थिक प्रभाव को मापा गया, क्योंकि इससे समय से पहले होने वाली मौतों के कारण आउटपुट का नुकसान हुआ और रुग्णता बढ़ी।

अध्ययन में कहा गया है कि ये मौतें पिछले साल देश में हुई कुल मौतों का 17.8 प्रतिशत थीं, जबकि आर्थिक नुकसान भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.36 प्रतिशत था। वायु प्रदूषण से भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में साल दर साल लगभग 0.56 प्रतिशत की कमी आ रही है, क्योंकि जीडीपी की गणना में शामिल वस्तुओं एवं सेवाओं पर वायु प्रदूषण नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। भारत में वायु प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित स्तर का लगभग 20 गुना और भारत के अपने मानकों से दो गुने से भी अधिक है। वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के साथ-साथ अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। प्रदूषण के लगातार गहराते संकट को देखते हुए अब तो यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि वायु प्रदूषण से होने वाला आर्थिक नुकसान 2024 तक भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के सपने पर भी पानी फेर सकता है। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण माना जाता है। यह दुनिया में असमय मृत्यु का चौथा सबसे बड़ा कारण है। ऐसा नहीं है कि प्रदूषण से होने वाले देश के लोगों के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान का राजनीतिक दलों और केंद्र व राज्य सरकारों को अंदाजा नहीं है, किन्तु क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के सामने राष्ट्रवाद बौना साबित हो रहा है। देश की तरक्की और निर्धारित आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है सरकारें राष्ट्रहित को सर्वोपरी रखें।

स्कूलों के निरीक्षण में प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर 73वें पायदान पर, DM-CDO और BSA से सबक नहीं ले रहे अधीनस्थ अधिकारी

परिवहन विशेष न्यूज

जिलाधिकारी हर माह स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। वह स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ ही कायाकल्प और मिड डे मिल को चरख रहे हैं। वहीं सीडीओ और बीएसए भी लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रही हैं। उसके बाद भी वरिष्ठ अधिकारियों से अधीनस्थ सबक नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की अक्टूबर माह की रिपोर्ट में मंडल में सबसे खराब स्थिति में गौतमबुद्ध नगर की है।

ग्रेटर नोएडा। जिले के चारों ब्लाक में संचालित सरकारी स्कूलों में निरीक्षण के लिए बनाई गई जिला और ब्लाक स्तरीय टीमें शिक्षा की गुणवत्ता और मिड डे मिल को जांचने के लिए नहीं निकल रही है।

स्कूलों में निरीक्षण नहीं होने के कारण प्रदेश में जिला 73वें पायदान पर आया है। दोनों टीमों के सदस्यों को हर महीने पांच से अधिक स्कूलों का निरीक्षण कर प्रेरणा एप पर अपडेट करना होता है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की अक्टूबर माह की रिपोर्ट में मंडल में सबसे खराब स्थिति में गौतमबुद्ध नगर की है।

अक्टूबर माह में 575 में से केवल 275 स्कूलों में ही जिला और ब्लाक स्तरीय टीम के सदस्यों ने निरीक्षण किया। 47.83 प्रतिशत स्कूलों का ही निरीक्षण किया गया। जबकि सबसे अधिक स्कूलों का निरीक्षण बागपत में किया गया। 590 में से 581 स्कूलों का निरीक्षण वहां की टीमों ने किया।

सितंबर में भी 56.17 प्रतिशत स्कूलों में ही निरीक्षण किया गया था। सितंबर में जिला 50वें पायदान पर था। 98 प्रतिशत से अधिक स्कूलों के निरीक्षण वाले जिलों को शासन की ओर से 10 अंक दिए जाते है, लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं होने के कारण जिले को कई महीनों से पिछड़ना पड़ रहा है।

जिला और ब्लाक स्तरीय टीम में ये सदस्य

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी टास्क फोर्स में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य/सचिव, जिला पूर्ति अधिकारी, सभी उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी शामिल हैं।

वहीं उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी टास्क फोर्स में उप जिलाधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सहायक विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, उपजिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य विकास अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक शामिल है। कई अधिकारियों ने तो अब तक एक भी स्कूलों का निरीक्षण नहीं किया है।

जिलाधिकारी से नहीं ले रहे अधीनस्थ सबक

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा हर माह स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। वह स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ ही कायाकल्प और मिड डे मिल को चरख रहे हैं। वहीं सीडीओ और बीएसए भी लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रही हैं। उसके बाद भी वरिष्ठ अधिकारियों से अधीनस्थ सबक नहीं ले रहे हैं।

टीम के सदस्यों की ओर से लगातार स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है। प्रेरणा पोर्टल पर निरीक्षण अपडेट नहीं हो पाए है। कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर निरीक्षण को तत्काल अपडेट किया जाए।

- मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी

एंबियंस मॉल के KFC में कार्यरत दो लड़कियों को कार ने कुचला, एक की मौत

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी 22 वर्षीय शिखा ने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली के रंगपुरी में किराये से रहती हैं। उनके साथ ही देवरिया की 22 वर्षीय दुर्गेश्वरी भी रहती थीं। दोनों गुरुग्राम के एंबियंस मॉल स्थित केएफसी में एक साल से खाना पैकिंग करने के काम में लगी थीं। उद्योग विहार पुलिस ने आरोपित कार चालक के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

गुरुग्राम। शंकर चौक के पास गुरुग्राम की तरफ से जा रही तेज रफ्तार कार ने हाईवे पर कर रही दो युवतियों को कुचल दिया। हादसे में एक युवती की मौत हो गई। दोनों युवतियां एंबियंस मॉल स्थित केएफसी में खाना पैकिंग विभाग में कार्यरत थीं। उद्योग विहार पुलिस ने आरोपित कार चालक के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

एक साल से खाना पैकिंग करने के काम में लगी थीं

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी 22 वर्षीय शिखा ने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली के रंगपुरी में किराये से रहती हैं। उनके साथ ही देवरिया की 22 वर्षीय दुर्गेश्वरी भी रहती थीं। दोनों गुरुग्राम के एंबियंस मॉल स्थित केएफसी में एक साल से खाना पैकिंग करने के काम में लगी थीं।

रविवार रात साढ़े नौ बजे वह ड्यूटी खत्म कर वापस घर जा रही थीं। इसी दौरान शंकर चौक पर हाईवे पर करते हुए गुरुग्राम की तरफ से आई काले कलर की कार ने दोनों युवतियों को कुचल दिया। आसपास के लोगों ने दोनों को पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

घटना की सूचना पर दोनों के परिवारवाले पहुंचे। हालत गंभीर होने पर दुर्गेश्वरी को सफदरजंग रेफर कर दिया गया। यहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उद्योग विहार थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया।

ड्यूटी पर जा रहे कंपनी कर्मी की वाहन की टक्कर से मौत

मोटरसाइकिल से ड्यूटी पर जा रहे एक निजी कंपनी के कर्मचारी की पीछे से आ रही एक कार की टक्कर से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बिहार के ताराखट के रहने वाले पप्पू राणा अपने साथी नवाब सिंह के साथ मंत्रा कंपनी में नाइट ड्यूटी करने जा रहे थे। त्रिवेणी होटल के पास पीछे से आई एक गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इससे पप्पू को सिर में ज्यादा चोट आई। दुर्घटना को अंजाम देने वाला गाड़ी चालक पप्पू को गाड़ी से मानेसर के ईएसआई अस्पताल ले गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पप्पू की मौत की सूचना के बाद चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। बिलासपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

17 हजार में बुकिंग कर फार्म हाउस में कर रहे थे दारू पार्टी, पुलिस ने दिल्ली के 7 लोगों को पकड़ा

भोंडसी थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि महेंद्रवाड़ा में एक फार्म हाउस में दारू पार्टी चल रही है। इस सूचना पर पुलिसकर्मी यहां छापा मारने पहुंचे। इस दौरान सात लोग शराब पी रहे थे। पुलिस को देखते ही सभी भागने लगे लेकिन सभी को पकड़ लिया गया। भोंडसी पुलिस ने छापेमारी कर फार्म हाउस के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया।

गुरुग्राम। भोंडसी थाना क्षेत्र के महेंद्रवाड़ा में एक फार्म हाउस में दारू पार्टी करने आए दिल्ली के सात लोगों को पकड़ लिया गया। भोंडसी पुलिस ने छापेमारी कर फार्म हाउस के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों ने बताया कि उन्होंने 17 हजार रुपये में फार्म हाउस की बुकिंग की थी। भोंडसी थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि महेंद्रवाड़ा में एक फार्म हाउस में दारू पार्टी चल रही है। इस सूचना पर पुलिसकर्मी यहां छापा मारने पहुंचे। इस दौरान सात लोग शराब पी रहे थे। पुलिस को देखते ही सभी भागने लगे, लेकिन सभी को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उनकी पहचान दिल्ली के वसंत कुंज निवासी रितुराज, मांटी, अमार्तमा राम सिंह, विजय प्रताप सिंह, अजीत कुमार, गुरुग्राम के साउथ सिटी एक निवासी सुधांशू और नोएडा के सलारपुर निवासी अतुल के रूप में की गई। पूछताछ में बताया कि इन सभी ने 17 हजार रुपये में फार्म हाउस की बुकिंग की थी।

फार्म हाउस का मैनेजर गिरफ्तार

पुलिस ने फार्म हाउस के मैनेजर योगेंद्र कुमार को भी पकड़ा। उससे शराब के सेवन कराने के लिए लाइसेंस मांगा गया तो वह कोई भी कागज नहीं दिखा सका। उसके विरुद्ध थाने में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यहां से भारी मात्रा में शराब की बोतले बरामद कीं।

ट्रांसपोर्टर के घर पर 50 लाख की चोरी, शादी के लिए रखे थे कैश

दिल्ली-एनसीआर में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं रही हैं। भैया दूज के अवसर पर पत्नी व बच्चों को ससुराल से वापस लेने गए ट्रांसपोर्टर के घर पर 50 लाख रुपये की चोरी वारदात सामने आई है। रविवार शाम को वह वापस लौटे तो देखा की मकान के मेन गेट पर लगा ताला टूटा हुआ था। घर के अंदर रखा सामान बिखरा पड़ा था।

गाजियाबाद। भैया दूज के अवसर पर पत्नी व बच्चों को ससुराल से वापस लेने गए ट्रांसपोर्टर के बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने 22 लाख की नकदी, लाइसेंसी रिवाल्वर, 16 तोला सोने के जेवर सहित लगभग 50 लाख रुपये का सामान चोरी कर लिया है। वारदात मोरटी गांव में शनिवार की रात हुई है। मामले की शिकायत पर नंदग्राम पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

ट्रांसपोर्टर रोहित चौधरी ने बताया कि भैया दूज के अवसर पर पत्नी राखी चौधरी बच्चों के साथ बुलंदशहर स्थित मायके गई थीं, शनिवार को वह उनको वहां से वापस लाने के लिए गए थे। इस दौरान घर पर ताला लगा था। रविवार शाम को वह वापस लौटे तो देखा की मकान के मेन गेट पर लगा ताला टूटा हुआ था।

नोएडा में कार में लगी आग, टला बड़ा हादसा

फेज-3 कोतवाली क्षेत्र के बाबा बालक नाथ मंदिर के पास मंगलवार दोपहर को एक कार में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक ऑल्टो कार की एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। सूचना पर आनन-फानन में पहुंची फायर सर्विस यूनिट ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। गनीमत यह रही है कि इसमें कोई जनहानि नही हुई।

नोएडा। फेज-3 कोतवाली क्षेत्र के बाबा बालक नाथ मंदिर के पास मंगलवार दोपहर को एक कार में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक, ऑल्टो कार की एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। सूचना पर आनन-फानन में पहुंची फायर सर्विस यूनिट ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है।

गनीमत यह रही है कि इसमें कोई जनहानि नही हुई है। आग लगने के चलते कुछ देर के लिए ट्रैफिक बाधित हुआ। हालांकि अब यातायात सुचारू रूप से संचालित हो रहा है।

नोएडा के सेक्टर-39 कोतवाली में गिझौड़ के राजा बाबू झा ने शिकायत दी है कि बीते दिनों उसका भाई राकेश कुमार झा ड्यूटी पूरी कर बाइक से घर लौट रहा था। सेक्टर-36 के पास अज्ञात वाहन के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसकी बाइक में टक्कर मारकर घायल कर दिया। उपचार के दौरान घायल की मौत हो गई पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात नियमों की दी जानकारी

यातायात पुलिस की रोड सेफ्टी सेल द्वारा प्रचार-प्रसार वाहनों पर एलईडी के माध्यम से जगतफार्म, एलजी गोलचक्कर, परीचौक, मकोडा गोलचक्कर, तिलपता गोलचक्कर एवं देवला पर आमजन व वाहन चालकों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी दी गई। एसीपी ट्रैफिक पवन कुमार दीक्षा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सूरजपुर एवं मिहिर भोज इंटर कालेज दादरी में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों व स्कूली वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देकर उनका पालन करने हेतु प्रेरित किया गया।

एसीपी श्यामजीत पर्मिला सिंह राजकीय महाविद्यालय सेक्टर-39 में छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी देकर उनका पालन करने हेतु प्रेरित किया गया। बोटनिकल गार्डन, सेक्टर-125, परीचौक, माडल टाउन, मेट्रो स्टेशन सेक्टर-51 व सेक्टर-52, सूरजपुर चौक, एलजी गोलचक्कर, सेक्टर-104, शाहबेरी में यातायात नियम का पालन करने के कमांड कंट्रोल सेंटर स्थित आइएसटीएमएस सीसीटीवी कैमरों के साथ स्थापित पीए सिस्टम की सहायता से आमजन एवं वाहन चालकों को यातायात के प्रति जागरुक किया गया।

इस दौरान बिना हेलमेट के 3248, बिना सीट बेल्ट के 109, विपरीत दिशा के 378, तीन सवारी के 53, मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर 29, बिना डीएल के 43, दोषपूर्ण नंबर प्लेट पर 67, रेड लाइट का उल्लंघन करने पर 81, नो पार्किंग के 455 सहित अन्य उल्लंघन पर 344 चालान किए गए। वहीं ध्वनि प्रदूषण के 13 व वायु प्रदूषण के 47 चालान किए गए। इस तरह कुल 4867 ई-चालान किए गए। नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 15 वाहनों को सीज किया गया।

बिना सरकारी संरक्षण के नहीं फलफूल सकता था यूपी में हलाल का धंधा

अजय कुमार

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कथित हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से 18 नवंबर 2023 को इस आशय का आदेश जारी किया जा चुका है।

खाद्य पदार्थों की गुणवता का पैमाना अब सिर्फ एफएसएसएआई सर्टिफिकेट नहीं रह गया है। एफएसएसएआई का मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस किसी भी ऐसे व्यक्ति या संगठन के लिए अनिवार्य है जो किसी भी प्रकार के फ़ूड बिज़नेस से जुड़ा है। प्रत्येक खाद्य व्यवसाय संचालक का कार्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रत्येक ग्राहक के लिए संतुष्टि प्रदान करने के लिए खाद्य गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना है। नियंत्रण प्रक्रियाओं के निर्माण में, भारतीय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन लगता है कि यह गुजरे जमाने की बात हो गई है। अब तो इस पर हलाल का ठप्पा भी लगा होना जरूरी है। इस हलाल के ठप्पे को सरकार भले नहीं मान्यता देती हो, लेकिन इस्लाम के नाम पर यह काला धंधा खूब फलफूल रहा था। इसका करोबार हजारों करोड़ तक पहुंच गया था और इसका पैसा कुछ धार्मिक ट्रस्टों और संस्थाओं के खाते में जा रहा था, जिसकी कहीं कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी, यह पैसा कहां खर्च होता था, इसकी भी किसी को जानकारी नहीं थी।

उत्तर प्रदेश में हलाल का एक काधा धंधा खूब फलफूल रहा था, लेकिन अब इस पर योगी सरकार की नजर लग गई है। गत दिनों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खाद्य पदार्थों सहित अन्य कई सामानों पर हलाल सर्टिफिकेट देने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए इस धंधे पर पूरी तरह से शिकंजा कस दिया। योगी सरकार के एक्शन लेते ही रातों-रात हलाल का ठप्पा लगा सामान बाजारों से गायब हो गया, क्योंकि हलाल का ठप्पा लगा सामान बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान था। मगर सवाल यह भी खड़ा होता है कि यदि हलाल सर्टिफिकेट बांटने का गोरख धंधा लम्बे समय स चल रहा था तो यूपी पुलिस और अन्य खुफिया एजेंसियों और खाद्य विभाग को इसकी भनक कैसे नहीं लग पाई। निश्चित ही हलाल का धंधा बिना सरकारी संरक्षण के इतना फलफूल नहीं सकता था। जरूरत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी है जो इस तरफ से आंखें मूंदे बैठे थे, क्योंकि हलाल पर जो भी कार्रवाई हो रही है, वह लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक व्यक्ति के एफआईआर लिखाने के बाद शुरू हुई है। बहरहाल, योगी सरकार द्वारा हलाल प्रमाण पत्र मामले में कार्रवाई किए जाने के साथ यूपी और उससे लगे राज्यों में हलाल और हराम को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। कोई हलाल के तार आतंकवाद और अन्य मतांतरण को बढ़ावा देने वाली घटनाओं से जोड़ कर देखा रहा है तो किसी को इसमें साम्प्रदायिता की बू आ रही है। इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। वहीं हलाल के धंधे में लगे लोगों को लगता है कि सरकार ने बिना सोचे समझे हलाल पर प्रतिबंद्ध लगाकर एक झटके में निर्यात को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि, हलाल का मामला यूपी तक ही सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में हलाल का ठप्पा लगाये जाने का खेल चल रहा है। हिंदू जनजागृति समिति लगभग दो साल से इसके खिलाफ अभियान चला रही है। इसको लेकर जमशेदपुर में समिति की सेमिनार-गोष्ठी भी हो चुकी है। आज भी कई राज्यों में हलाल सर्टिफिकेट के मिठाई-नमकीन सहित कॉस्मेटिक के उत्पाद बिक रहे हैं।

गौरतलब है कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कथित हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से 18 नवंबर 2023 को इस आशय का आदेश जारी किया जा चुका है। लखनऊ में 17 नवम्बर 2023 को हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी और जमीयत उलेमा-ए-हिन्द सहित कुछ अन्य संस्थाओं एवं लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें हलाल सर्टिफिकेट को हिन्दू आस्था पर आघात बताते हुए इससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने की माँग की गई थी। केस दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश शासन ने अगले दिन 18 नवम्बर को हलाल के बजाय एफएसएसआई एवं एफएसएसएआई के प्रमाण पत्र को मानकों के लिए उचित बताया था। इस केस में दर्ज हुई एफआईआर में हलाल इंडिया के चेन्नई और मुंबई कार्यालय के साथ जमीयत उलेमा ए हिन्द के दिल्ली और मुंबई ऑफिस को नामजद किया गया था। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेट को बढ़ावा देने वाली कुछ अज्ञात कम्पनियाँ, राष्ट्र विरोधी साजिश रचने वाले कुछ अन्य अज्ञात लोग, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे अज्ञात समूह और जनआस्था से खिलवाड़ करने के साथ दंगे करवाने की साजिश रच रहे कुछ अज्ञात लोगों को नामजद किया गया है।

इस विंटर सीजन Renault India का अपने ग्राहकों को जबरदस्त ऑफर, कार सर्विस से लेकर स्पेयर्स पार्ट्स पर मिलेगा लाभ

Renault India ने देशभर में अपने ग्राहकों के लिए विंटर सर्विस कैंप की घोषणा की है। फ्रांसीसी ऑटो दिग्गज ने कहा है कि उसकी कारों के मालिक भारत भर में किसी भी रेनो-अधिकृत सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं और अभियान के तहत अपने वाहन की जांच और सर्विस करा सकते हैं। आइए कंपनी की पूरे प्लान के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। Renault India ने देशभर में अपने ग्राहकों के लिए विंटर सर्विस कैंप की घोषणा की है। फ्रांसीसी वाहन निर्माता ने कहा है कि इस पहल के तहत उसके ग्राहक 20 नवंबर से 26 नवंबर 2023 तक कारों की सर्विस पर कई तरह के डिस्काउंट और छूट का लाभ उठा सकते हैं। रेनो का दावा है कि कंपनी की ओर से पार्ट्स, एक्सेसरीज और लेबर चार्ज पर डिस्काउंट दिया जाएगा। ये लाभ पूरे भारत में Renault India के शोरूम पर उपलब्ध होगा।

विंटर कैंप का कैसे उठाएं लाभ

फ्रांसीसी ऑटो दिग्गज ने कहा है कि उसकी कारों के मालिक भारत भर में किसी भी रेनो-अधिकृत सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं और अभियान के तहत अपने वाहन की जांच और सर्विस करा सकते हैं। ऑटो कंपनी ने यह भी कहा कि ग्राहक चुनिंदा पार्ट्स पर 10 प्रतिशत की छूट, चुनिंदा एक्सेसरीज पर 50 प्रतिशत तक की छूट और लेबर चार्ज पर 15 प्रतिशत की छूट के साथ इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं।

रेनो का दावा है कि वह अपने ग्राहकों को स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट के साथ-साथ कॉम्प्लीमेंट्री कार वॉश की पेशकश कर रही है। इसके अलावा, जो ग्राहक अपनी कार की वारंटी बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें वारंटी पैकेज और RSA पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

कंपनी ने क्या कहा?

कंपनी की इस पहल पर बोलते हुए वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग, सुधीर मल्होत्रा ने कहा कि विंटर कैंप के साथ, ऑटो निर्माता का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण सर्दियों के मौसम के दौरान रेनॉल्ट वाहनों के प्रदर्शन और सुरक्षा को अनुकूलित करना है। उन्होंने आगे कहा, ₹हमारे कुशल तकनीशियनों द्वारा किए गए कार चेक-अप और आकर्षक ऑफर के माध्यम से हम अपने ग्राहकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बनाने का प्रयास करते हैं।

टेस्ला भारतीय बाजार में जल्द कर सकती है एंट्री, साल 2024 से इलेक्ट्रिक वाहनों का इंपोर्ट शुरू होने की उम्मीद

दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla भारतीय ईवी बाजार में प्रवेश करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौते के करीब पहुंच रही है। जनवरी 2024 में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में टेस्ला के भारतीय बाजार में प्रवेश की एक ठोस तस्वीर हो सकती। उम्मीद है कि टेस्ला देश में शुरुआती न्यूनतम 2 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी।

नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla, भारतीय ईवी बाजार में प्रवेश करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौते के करीब पहुंच रही है। ऑटोमेकर भारत सरकार के साथ एक समझौते पर काम कर रहा है, जो ईवी निर्माता को 2024 से देश में अपनी इलेक्ट्रिक कारों को शिप करने की अनुमति देगा। साथ ही, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑटोमेकर 2025 तक देश में एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करेगा।

Tesla कब आएगी भारत?

जनवरी 2024 में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में टेस्ला के भारतीय बाजार में प्रवेश की एक ठोस तस्वीर हो सकती। टेस्ला कथित तौर पर भारत में अपनी पहली विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों पर विचार कर रही है। हालांकि, ईवी निर्माता ने अभी तक उस स्थान को अंतिम रूप नहीं दिया है, जहां वह प्लांट स्थापित करेगा। दिलचस्प बात यह है कि उपरोक्त तीनों राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों और निर्यात के लिए अच्छी तरह से स्थापित ईको-सिस्टम है।

ये है कंपनी का प्लान

रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि टेस्ला देश में शुरुआती न्यूनतम 2 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी। इसके अलावा कंपनी, कथित तौर पर स्थानीय निर्माताओं से ऑटो कंपोनेंट की खरीद बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है और इन ऑटो पार्ट्स की कीमत 15 अरब डॉलर तक होगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस दशक के अंत में अपनी कारों को स्थानीय स्तर पर बनाने के अलावा, टेस्ला उत्पादन लागत को कम करने के प्रयास में अपने ईवी के लिए भारत में कुछ बैटरी पैक भी बनाएगी।

कहां फंस रहा है पेंच?

सरकार द्वारा लगाए गए उच्च आयात शुल्क के कारण टेस्ला अपनी इलेक्ट्रिक कारों को सीधे भारत में आयात नहीं करता है। टेस्ला ने कई बार भारत सरकार से आयात शुल्क कम करने की अपील की है, जिससे वह लोकल प्लांट स्थापित करने से पहले अपनी कारों को पूरी तरह से निर्मित इकाई (सीबीयू) मार्ग के माध्यम से ला सके। दूसरी ओर, भारत सरकार ने हमेशा कहा है कि टेस्ला को पहले भारत में निवेश करना चाहिए।

हयूंडई टकसन फेसलिफ्ट के नए लुक से उठा पर्दा, इन बदलावों के साथ 2024 में भारत आएगी ये प्रीमियम एसयूवी

Hyundai Tucson facelift में मामूली बदलाव किए गए हैं। दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता की हाल ही में लॉन्च हुई अधिकांश अन्य फेसलिफ्टेड कारों के विपरीत टुसों में अपडेट काफी कम हैं। नई हुंडई टुसों को केबिन के अंदर भी कई अपडेट दिए गए हैं। इसमें एक अपडेटेड 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और पारंपरिक डैशबोर्ड शामिल है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। Hyundai ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में लॉन्च से पहले अपनी लग्जरी एसयूवी Tucson facelift से पर्दा उठाया है। ये एसयूवी बाहरी और केबिन के अंदर कुछ अपडेट के साथ आती है, जो इसे मौजूदा मॉडल की तुलना में अधिक प्रीमियम बनाते हैं।

उम्मीद है कि नई Hyundai Tucson यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे बाजारों में लॉन्च होने के बाद 2024 में किसी समय भारत में लॉन्च होगी। आइए, इसकी डिजाइन, डायमेंशन और अन्य डिटेल के बारे में जान लेते हैं।

डिजाइन

Hyundai Tucson facelift में मामूली बदलाव किए गए हैं। दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता की हाल ही में लॉन्च हुई अधिकांश अन्य फेसलिफ्टेड कारों के विपरीत टुसों में अपडेट काफी कम हैं। इस एसयूवी में नए डिजाइन का फ्रंट ग्रिल दिया गया है, जो पहले से थोड़ा शार्प है और नए इंटरनल के साथ आता है।

विशिष्ट रूप से ये एक डेवलप्ड पैरामीट्रिक डायनेमिक्स डिजाइन है, जिसे हुंडई डिजाइन एलीमेंट के रूप में तुरंत पहचाना जा सकता है। इसका हेडलैंप क्लस्टर अपरिवर्तित रहता है, लेकिन ग्रिल के अंदर एकीकृत एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स अपडेटेड नजर आ रही हैं। बम्पर पर सेंट्रल एयर इनटेक भी थोड़ा अपडेटेड दिखता है। ये एसयूवी नए अलॉय व्हील्स पर चलती है। उम्मीद है कि इसके रियर प्रोफाइल में थोड़ा अपडेटेड बम्पर और टेललाइट्स मिलेंगे।

इंटीरियर

नई हुंडई टुसों को केबिन के अंदर भी कई अपडेट दिए गए हैं। इसमें एक अपडेटेड 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और पारंपरिक डैशबोर्ड शामिल है। डैशबोर्ड पर एक पैनोरमिक कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसमें 12.3 इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और मैचिंग 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है।

नए सेंटर कंसोल के साथ अन्य अपडेट में फिर से डिजाइन किया गया स्विचगियर और ट्रांसफर्ड एसी वेंट शामिल हैं। हुंडई ने सेंटर कंसोल पर एक वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग डॉक और दो कप होल्डर पेश किए हैं। पैडल शिफ्टर को भी स्टीयरिंग कॉलम में ले जाया गया है और एसयूवी को अब कई फिजिकल कंट्रोल मिलते हैं।

इंजन

हुंडई ने अपडेटेड Tucson facelift के पावरट्रेन के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया है। उम्मीद है कि फेसलिफ्टेड एसयूवी मौजूदा मॉडल के समान पावरट्रेन के साथ आएगी।

बर्बादी का दूसरा नाम है मुफ्तखोरी

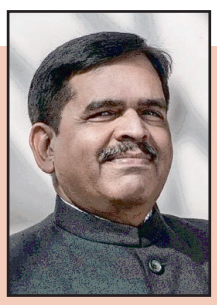

डा. अश्विनी महाजन

बढ़ते कर्ज न केवल राजकोषीय असंतुलन पैदा कर रहे हैं, बल्कि कल्याणकारी योजनाएं चलाने की क्षमता को भी प्रभावित कर रहे हैं'

नवंबर 7 से शुरू होकर 30 नवंबर 2023 तक देश के पांच महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव हमारे लोकतंत्र के उत्सव के रूप में जाने जाते हैं। आजादी के बाद चुनावों की सतत प्रक्रिया के चलते भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रीय देश के रूप में उभरा है। यह समय है राजनीतिक दलों द्वारा अपने-अपने चुनाव घोषणापत्रों के माध्यम से मतदाताओं को अपने दलों की नीतियों और प्रस्तावित कार्यक्रमों से अवगत करवाने का। इतिहास में सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने वादों से लुभाने का प्रयत्न करते ही रहे हैं, लेकिन पिछले लगभग डेढ़ दशक में चुनावी वादों का प्रकार बदला है। इन वादों में नीतियों और कार्यक्रमों की बजाय नकद राशि हस्तांतरण और मुफ्त की स्कीमों की घोषणाएं प्रमुखता से होने लगी हैं। महिलाओं, किसानों, विद्यार्थियों और कई बार अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर वर्गों को नकद हस्तांतरण, समस्त जनता को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त यात्रा समेत कई मुफ्तखोरी की स्कीमों की घोषणाएं अब एक आम बात हो गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के कर्ज माफ करने के अलावा मुफ्त बिजली, गैस सिलेंडर की सब्सिडी, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह, युवाओं को 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के अलावा कई अन्य मुफ्त की स्कीमों की घोषणा की है। इसी प्रकार की घोषणाएं अलग-अलग राजनीतिक दलों द्वारा की गई हैं। मतदाताओं को रिझाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में विचार करने का विषय है कि क्या यह हमारे लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है। क्या हमारी सरकारें इन मुफ्त स्कीमों के लिए धन जुटा पाएंगी? कहीं राज्य सरकारों पर कर्ज का बोझ तो नहीं बढ़ जाएगा? इन मुफ्त की योजनाओं का सरकारी योजनाओं, सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च और उनके स्तर पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? इन सभी प्रश्नों पर विचार करना जरूरी हो गया है।

अन्य देशों के उदाहरण : दुनिया के कई देशों में मुफ्तखोरी के कारण सरकारी कर्ज के बढ़ने और कई देशों के तो उसके कारण बर्बाद होने के भी कई उदाहरण मिलते हैं। वेनेजुएला और श्रीलंका इत्यादि के उदाहरणों से पता चलता है कि उन जैसे धनाढय देश भी मुफ्तखोरी की गलत आर्थिक नीतियों के चलते गरीब देशों से भी बदतर हालत में पहुंच सकते हैं, तो पाकिस्तान सरीखे विकासशील देशों की बिसात ही क्या है। वर्तमान में कल्याणकारी राज्य के नाम पर मुफ्त की स्कीमों के कारण कई अमीर देशों की भी एक लंबी सूची है, जो आज भारी कर्ज में डूबे हुए हैं और अब वे इन स्कीमों को चलाने में सक्षम नहीं हैं।

राज्यों पर बढ़ता कर्ज : लेकिन मुफ्तखोरी की यह बीमारी अब भारत के कई राज्यों में फैलती जा रही है। इस माह होने वाले चुनावों में तो राजनीतिक दलों ने मुफ्तखोरी की योजनाओं की घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। मुफ्त बिजली, मुफ्त यातायात, महिलाओं को अनुदान राशि, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता इत्यादि के साथ-साथ मुफ्त वाहन और कई अन्य मुफ्तखोरी की स्कीमों के बारे में हम रोज सुन रहे हैं। कुछ समय पहले भारतीय रिजर्व बैंक और भारत के महालेखाकार एवं अंकेक्षक (कैग) ने अपनी-अपनी रिपोर्टों में मुफ्तखोरी के कारण राज्यों पर बढ़ते कर्ज के बारे में आंकड़े प्रकाशित किए हैं और यह चिंता व्यक्त की है कि जहां-जहां मुफ्तखोरी की स्कीमें ज्यादा चल रही हैं, वहीं-वहीं पर राज्यों पर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार किसी भी राज्य में ऋण-जीएसडीपी (राज्य का सकल घरेलू उत्पाद) का लक्षित अनुपात 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन कैग का कहना है कि देश के अधिकांश राज्यों में यह अनुपात इस लक्षित अनुपात से कहीं ज्यादा है। पंजाब में यह 48.98 प्रतिशत, राजस्थान में 42.37 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 37.39 प्रतिशत, बिहार में 36.73 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 35.30 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 31.53 प्रतिशत, तेलंगाना में 27.80 प्रतिशत, तमिलनाडु में 27.27 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 26.47 प्रतिशत तक पहुंच गया है। और यदि राज्य के सरकारी उद्यमों और राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को भी शामिल कर लिया जाए तो 2020-21 तक राजस्थान में ऋण जीएसडीपी अनुपात 54.94 प्रतिशत और पंजाब में तो यह 58.21 प्रतिशत तक पहुंच चुका था। आंध्रप्रदेश में भी यह 53.77 प्रतिशत आकलित किया गया है। इसके बाद तेलंगाना में यह 47.89 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 47.13 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल और बिहार में भी यह क्रमशः 40.35 प्रतिशत और 40.51 प्रतिशत है और तमिलनाडु में यह 39.94 प्रतिशत है। कैग का यह भी कहना है कि राज्यों का कर्ज लक्षित अनुपात की तुलना में लगातार बढ़ता जा रहा है। यह राज्यों के लिए ही नहीं, देश के लिए भी चिंता का विषय है। आंध्र प्रदेश के बारे में रिजर्व बैंक का कहना है कि पंजाब के बाद आंध्रप्रदेश मुफ्त की योजनाओं पर खर्च करने वाला देश का दूसरा ऐसा राज्य है। गौरतलब है कि पंजाब में कुल कर राजस्व का 45.5 प्रतिशत मुफ्त की योजनाओं पर खर्च होता है और आंध्र प्रदेश में 30.3 प्रतिशत। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो पंजाब में राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.7 प्रतिशत मुफ्त की योजनाओं में खर्च होता है तो आंध्र प्रदेश में 2.1 प्रतिशत। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सब्सिडी पर खर्च कर राजस्व का 28.8 प्रतिशत, झारखंड में यह 26.7 प्रतिशत है। गौरतलब है कि कैग के आकलन के अनुसार उन राज्यों पर कर्ज ज्यादा है, जहां मुफ्त की स्कीमों पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है। इसमें सबसे ऊपर पंजाब और आंध्रप्रदेश हैं जहां कुल राजस्व का भारी हिस्सा मुफ्त की योजनाओं पर खर्च होता है। आंध्र प्रदेश के अलावा दक्षिण का एक अन्य प्रांत तमिलनाडु है जो मुफ्त की योजनाओं पर खर्च करता है।

जरूरी मदों पर खर्च में कटौती : जब कोई प्रांत मुफ्त की स्कीमों पर अपने कर राजस्व का इतना बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है तो स्वाभाविक रूप से आवश्यक सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसका पूंजीगत खर्च कम हो जाता है। राज्य सरकार पर कर्ज बढ़ता चला जाता है, जिसके चलते भविष्य में भी सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ यातायात और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। किसी भी राज्य के विकास के लिए जरूरी है कि उसमें निवेश बढ़े। इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभाव में निवेश प्रभावित होता है और उसके कारण राज्य का विकास भी। जरूरी है कि राज्यों द्वारा दी जा रही मुफ्त की स्कीमों पर अंकुश लगाकर देश के विकास को गति दी जाए।

रेटिंग पर भी असर : हमें समझना होगा कि भारत राज्यों का एक संघ है, इसलिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के ऋण मिलाकर संपूर्ण सरकार के ऋण माने जाते हैं। जहां एक तरफ केन्द्र सरकार कोरोना काल में अपने ऋण जो सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के 61 प्रतिशत तक पहुंच गया था, को 56 प्रतिशत तक घटाने में सफल हो चुकी है, लेकिन विभिन्न राज्य सरकारों के ऋण राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में संपूर्ण सरकार पर कर्ज बढ़ने के कारण देश की आर्थिक रेटिंग घटती जा रही है। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो हमारे देश को निवेश मिलने में तो कठिनाई होगी ही, हमारी कंपनियों और सरकार के द्वारा जो विदेशों से ऋण लिया जाता है उस पर भी ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। यानी बढ़ते कर्ज न केवल राजकोषीय असंतुलन पैदा कर रहे हैं, बल्कि राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाएं चलाने की क्षमता को भी प्रभावित कर रहे हैं और देश व उद्योग के विकास के लिए भी मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं। राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते देश को मुश्किल में न डाल सकें, इसके लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। राजनीतिक कारणों से विधायिका और सरकारी तंत्र शायद इस काम में सफल न हो सके, लेकिन हमारे लोकतंत्र के अन्य स्तंभों जैसे न्यायपालिका और मीडिया को इस हेतु आगे आना होगा।

संपादक की कलम से

क्रिकेट की अनहोनी

टीम इंडिया 'अजेय चैम्पियन' नहीं बन सकी। एकदिनी क्रिकेट का विश्व चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया बना, जो पांच बार इस खिताब को जीत चुका था और फाइनल मुकाबले के दबावों तथा मनोविज्ञान को अच्छी तरह जानता था। टीम इंडिया कई फाइनल मुकाबले खेल चुकी है, लेकिन आखिरी चरण में उसके हाथ-पांव फूलने लगते हैं, नतीजतन 2013 में 'आईसीसी चैम्पियन्स ट्रॉफी' जीतने के बाद आज तक टीम इंडिया कोई विश्व-खिताब नहीं जीत पाई है। बेशक 'विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप' हो या टी-20 मुकाबलों के फाइनल हों, टीम इंडिया की परिणति और नियति 'उपविजेता' वाली हो गई है। बेशक टीम इंडिया ने एकदिनी क्रिकेट के विश्व कप में 10 लीग मैच और एक सेमीफाइनल मैच एकतरफा और निरंतर जीते थे, लिहाजा 'अजेय' मानना गलत नहीं था। हमने ऑस्ट्रेलिया समेत विश्व की तमाम श्रेष्ठ टीमों को पराजित किया। यह कोई तुक्का नहीं था। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज एवं 'प्लेयर ऑफ दि टूर्नामेंट' विराट कोहली (765 रन), सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मुहम्मद शमी (24 विकेट) और बुमराह (20 विकेट) और सर्वश्रेष्ठ कप्तान रोहित शर्मा (597 रन) आदि के सम्मान-पुरस्कार भी हमारे हिस्से आए, लेकिन कुछ तो गलत गणनाएं हुई थीं कि हम 'विश्व विजेता' नहीं बन पाए। विश्व के नंबर वन बल्लेबाज आज भी शुभमन गिल हैं और चौथे-पांचवें स्थान पर क्रमशः विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं। सिराज आज भी विश्व के नंबर 2 के गेंदबाज हैं। बल्लेबाजों के वर्ग में पहले पांच स्थान पर ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं है।

टीम इंडिया ने विश्व कप में कुल 3160 रन बनाए हैं। यह भी सर्वाधिक हैं। ये कोई सामान्य आंकड़े नहीं हैं। फिर भी सवाल हो सकता है कि फाइनल में रवीन्द्र जडेजा और कुलदीप यादव की स्पिन गेंदबाजी का वह करिश्मा कहां काफूर हो गया, जो पूरे टूर्नामेंट के दौरान आतंक और आश्चर्य बना हुआ था? सवाल हमारी धीमी बल्लेबाजी पर भी स्वाभाविक है, क्योंकि तीन विकेट गिरने के बाद हमारे बल्लेबाजों ने 20 ओवर में सिर्फ 72 रन ही बनाए? खेल के 40 ओवर में एक भी छक्का नहीं लगा। आखिरी 10 ओवर में 5 विकेट खोकर 43 रन ही बन पाए! सूर्यकुमार यादव अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी साबित नहीं कर पाए। दिलचस्प यह है कि बुमराह और शमी ने 47 रन पर ही ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट उखाड़ दिए थे, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड (137 रन) और लाबुशेन (नाबाद 58 रन) की शतकीय साझेदारी ने हमारा सपना 'छन' से तोड़ दिया। 'अजेय चैम्पियन' बनने की उम्मीदें और सच भी छीन लिए। आघात जरूर लगा है, लेकिन यह निराशा का वक्त नहीं है। इसकी समीक्षा भी खुद हमारे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को करनी चाहिए और आगे बढना चाहिए।

अभी तो हमारी अपनी जमीन पर 'विश्व विजेता' ऑस्ट्रेलिया के साथ टीम इंडिया को टी-20 की सीरीज खेलनी है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका भी जाना है। 2025 में 'चैम्पियन्स ट्रॉफी' प्रतियोगिता विश्व कप से कमतर नहीं है। यह हमारे खिलाडियों की टांग खींचने का भी वक्त नहीं है। टीम इंडिया के 11 चेहरों ने मैदान पर विलक्षणता दिखाई है और भारत के बारे में बड़ी तस्वीर पेश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक ही कहा है कि हमें आज भी अपनी टीम पर गर्व है। हम आज भी टीम के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। यह खेल-भावना का संदर्भ और सरोकार है। कमोबेश 19 नवम्बर हमारा दिन नहीं था। इस खेल ने यह भावना पेश की है कि भारत समग्रता में एक राष्ट्र है।

राय

नए भविष्य के लिए

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक ने सुक्खू सरकार के इरादों की पुनः पुष्टि करते हुए कुछ फैसले ऐसे भी लिए जिनसे न्याय फिर से परिभाषित होता है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल फिर लौट रहा है, क्योंकि सरकार की इच्छाशक्ति अपने निर्णयों के स्तंभों को ठोस जमीन पर खड़ा करना चाहती है। प्रायः कानून की चारदीवारी को राजधानी शिमला के वजूद में देखा गया है, जहां प्रदेश की उच्च अदालत का सिंहासन बोलता है। कर्मचारी मामले भी अपनी घुटन मिटाने के लिए कानून की आबोहवा में, शिमला की दूरबीन से जो देखते रहे, उन्हें फिर से प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के दायरे में लाने का संकल्प प्रतिपादित हो रहा है। हालांकि कर्मचारी मसलों में सरकारों के सौहार्द परवान चढ़ते रहे, लेकिन कानून के दायरे में हिफाजत का सफर बार-बार बदला। कभी सारे कर्मचारी विषय अदालत की फरियाद में हुजूम बन गए, तो कभी प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने अपने ढांचे में फरियाद को मंडी व धर्मशाला तक पहुंचा दिया, ताकि मामलों को सुनने का आधार पूरे प्रदेश की तासीर को संबोधित कर सके। उम्मीद है एक बार फिर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के माध्यम से कर्मचारी मसले, हिमाचल के क्षेत्रीय अपेक्षाओं के साथ त्वरित राहत का जाम पिएंगे। कर्मचारियों के लिए अपनी पैरवी के सबूत उठा-उठा कर शिमला में जाकर जंग जीतना आसान नहीं, लेकिन ट्रिब्यूनल के माध्यम से यही सफर अगर धर्मशाला-मंडी में कट जाए, तो बोझ भी घट जाएगा। बहरहाल यह मामला प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के औचित्य को सिद्ध कर रहा है, तो न्याय की इसी दलील पर हाई कोर्ट की सर्किट बैंच या स्थायी बैंच का प्रश्न भी अकसर उतावला हो जाता है। तर्क इसी क्रम और ताकत से ताकते रहे हैं और गुजारिश यह रही कि कम से कम हाई कोर्ट की एक अदद सर्किट बैंच धर्मशाला के लिए मंजूर हो जाए। पिछले चालीस सालों से प्रयासरत प्रदेश के एक बड़े भू भाग के लिए न्याय की यह मांग फिलहाल सियासी इच्छाशक्ति की मोहताज रही है, जबकि हिमाचल विधानसभा का एक पूरा शीतकालीन सत्र इसी तर्क की गवाही में तपोवन में आयोजित होने लगा है। इस बार 19 से 23 दिसंबर तक यही सत्र फिर से हिमाचल की नब्ज की परख करेगा। बहरहाल मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री की ऊर्जा व उनके बहुप्रतीक्षित फैसलों का इंतजार था और इस दृष्टि से ब्यास बेसिन में 50 क्रशर को फिर से शुरू करने की घोषणा ने कई तरह के आर्थिक संवेग पैदा किए हैं। बरसात के महीनों ने सरकार को बाध्य कर दिया था कि ऐसे फैसले की हूक में मनोरथ कमाया जाए, लेकिन जीवन रुकता कहां है। इनसान हमेशा अपनी ही हानियों की भरपाई में उम्र लगा देता है, दर्द के अध्यायों को फाड़ देता है या उसी पहाड़ से टकराता रहता है जो सदियों से टूट रहा है। बेशक ब्यास नदी के तट इस बार खूब रोए और बर्बादी के आलम में कई कश्तियां टूटी भीं, लेकिन प्रकृति की साझी विरासत में सिर्फ एक कहर ही नहीं चुना जा सकता। बेशक कुछ कसूरवार क्रशर पूरी नदी के आस्तीन में छुपे हुए सांप हैं, लेकिन खनन की शर्तों में कुछ तो औपचारिकताओं से बंधे थे। खैर अब तीन महीने की शून्यता के बाद फिर से रेत-बजरी घर की बुनियाद या तरक्की की ताल ठोंकेगी। इस निर्णय की कवायद में कुछ देरी जरूर हुई, लेकिन उम्मीद है कि आइंदा खनन के वैज्ञानिक, प्राकृतिक व भौतिक अपेक्षाओं को याद करके ही कदम उठाए जाएंगे। हिमाचल में वर्षा से हुई हानि के लिए केवल किसी एक कारण पर ही फैसले नहीं लिए जा सकते, बल्कि एक संतुलन बनाने की जरूरत है। हिमाचल में अतिक्रमणकारी शक्तियों ने जिस तरह नदी-नालों, घाटियों, कूहलों और जल निकासी की प्राकृतिक रूपरेखा को उखाड़ा है, उसके कारण खतरे उभरे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के वर्तमान से भविष्य को बचाने और पीड़ितों को फिर से बसाने के लिए खनन की परिपाटी को सुदृढ़ और सतर्क बनाने की जरूरत है।

चंदरेयां नोटां ने मेरा चन्न परदेसी कीता

प्रो. सुरेश शर्मा

क्या भारत में संसाधनों तथा योग्यतानुसार सैलरी पैकेज की उपलब्धता नहीं हो सकती? भारत से प्रतिभाओं का पलायन रोकना होगा'

इस आलेख का शीर्षक आम तौर पर ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, क्योंकि ट्रक का ड्राइवर परिवार के भरण पोषण के लिए हमेशा घर से दूर तथा सफर में ही रहता है। लगभग दो-तीन दशक पूर्व यह बात इसलिए समझ नहीं आती थी क्योंकि ज्ञान, अनुभव और समझ भी कम थी। उस समय आबादी भी अधिक नहीं थी तथा गरिमापूर्ण तरीके से भरण-पोषण के अवसर भी मौजूद थे। घर के युवा तथा बड़े अपने गांव-शहर के आसपास ही मौजूद रहते थे। कोई न कोई काम-धंधा तथा नौकरी करने के बाद शाम को या सप्ताह के अंत में घर आ जाते थे। गांव-मुहल्ले में गिना-चुना सैनिक, इंजीनियर, रेलवे, कारखाने तथा फैक्टरी या किसी अन्य व्यवसाय में काम करने वाला व्यक्ति ही बाहर किसी देश तथा प्रदेश में होता था अन्यथा शिक्षक, क्लर्क, सिपाही, फारेस्ट गार्ड, मैकेनिक, कारपेंटर, चपरासी तो लगभग प्रत्येक परिवार में मौजूद रहता था। परिवारों का आकार बड़ा होता था। परिवार में आठ-दस भाई-बहन होना सामान्य था। रोजगार के अवसर उपलब्ध थे, परन्तु बहुत शिक्षित तथा व्यवसाय अनुसार योग्यता पूर्ण करने वाले लोग बहुत कम मिलते थे। बुजुर्ग अपने किसी लाडले पुत्र को अधिक नहीं पढ़ाते थे। उसे घर गृहस्थी, खेती बाड़ी तथा परिवार समाज के व्यवहार की दृष्टि से शिक्षण-प्रशिक्षण देते थे। परिवार में नौकरी करने वाले घर चलाने वाले व्यक्ति तथा उसके परिवार का पूरी तरह से ध्यान रखते। घर के बुजुर्ग भी संवेगात्मक, भावनात्मक, सुरक्षात्मक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से सन्तुष्ट रहते। घर-परिवार तथा रिश्तेदारी में सरकारी नौकरी करने वालों की शान ही निराली थी। गांव तथा समाज के लोगों को अपने मित्र-सज्जन, भाई-बन्धु से आशा भी होती थी। सब अवसरों पर नौकरीशुदा व्यक्ति का आदर सम्मान होता था। परिवार, गांव तथा समाज में हर व्यक्ति की पहचान तथा मान-सम्मान था।

बहुत अधिक इच्छा, आशा, अपेक्षा तथा पैसे की भूख भी नहीं होती थी। बाहर से कोई परदेसी, अप्रवासी तथा कोई बाहरी व्यक्ति कामकाज के लिए नहीं आता था। दूरसंचार तथा आने-जाने के संसाधन सीमित थे। सरकारी रोजगार के अवसर भी उपलब्ध थे। संसाधनों के अभाव में जीवन कष्टदायक तो था, फिर भी शान्ति, संतुष्टि तथा संतोष था। कुछ दशकों के उपरांत घर-परिवार, समाज, प्रांत, देश तथा विदेश में ऐसी परिवर्तन की हवा चली कि सब कुछ बदल गया। सामाजिक आचार-व्यवहार, साधन, संसाधन, व्यक्ति की सोच तथा व्यवस्थाओं की नीतियों में परिवर्तन हुआ। कुछ तो हमने दुनिया को मुट्ठी में कर लिया और कुछ दुनिया की मु_ी में हो गए। वैश्विक स्तर पर शिक्षा, आर्थिकी, संसाधन, विज्ञान, संचार, तकनीक, भौतिकवाद नीतियों ने हमारे जीवन में आशातीत परिवर्तन कर दिया। इस परिवर्तन से जहां हमारी जीवन शैली बदल गई, वहीं हम ही अपने से तथा अपनों से ही दूर होते गए। हमारा सामान्य तथा प्राकृतिक जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। परिवार, गांव तथा समाज टूटते तथा बिखरते गए। परिणामस्वरूप नई सोच, नया व्यवहार, नई संस्कृति तथा सभ्यता का जन्म हुआ। हम अपने आप तथा अपने परिवार तक सीमित तथा संकुचित होते गए। सामाजिक तथा सामूहिक सरोकार लगभग समाप्त ही हो गए। हम व्यक्तिवादी, स्वार्थी, सीमित तथा संकुचित हो चुके हैं। चारों ओर छीना-झपटी, अवसरवादिता तथा असंतोष व्याप्त है। खुमार बाराबंकवी का एक शे'र याद आ रहा है : 'चरागों के बदले मकां जल रहे हैं/ नया है जमाना, नई रौशनी है।' वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में हर परिवार में एक या दो बच्चे हैं। छोटे से बड़ा व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी और महंगी शिक्षा देने को प्रयासरत तथा प्रतिबद्ध है। माता-पिता बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। व्यवस्थाओं के प्रयासों से शिक्षा में गुणवत्ता बहुत दूर होती गई। कार्य संस्कृति लगभग समाप्त ही है। सरकारी उपक्रमों में रोजगार उपलब्ध ही नहीं। अगर किसी को मौका मिलता है तो लोग काम नहीं करना चाहते। बहुत ही कम लोग ईमानदारी तथा संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं।

जो व्यक्ति समर्पित भाव से कार्य करना चाहता है, उसकी कोई पहचान नहीं है। जिम्मेदारी तथा कर्मठता से कार्य करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। जान-पहचान तथा प्रभावशाली व्यक्तियों का बोलबाला हो गया है। रोजगार के अवसर न के बराबर हैं। जहां रोजगार उपलब्ध है, वहां सामान्य रूप से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों तथा व्यवस्थाओं का हस्तक्षेप हो ही जाता है। योग्यता को दरकिनार होते देखा जाता है। किसी भी कीमत पर हम अवसरों को हथियाना चाहते हैं। नई पीढ़ी को विषय-विकारों तथा नशों ने घेर रखा है। अच्छी शिक्षा तथा संस्कारों से युक्त कुछ युवा बहुत ही प्रखर, प्रतिभाशाली तथा योग्य हैं। बहुत संस्कारी तथा ज्ञान-ध्यान रखते हैं। महंगी शिक्षा प्राप्त इन योग्य तथा प्रखर बुद्धि से युक्त युवाओं को घर के आसपास रोजगार उपलब्ध नहीं हैं। सरकारों तथा व्यवस्थाओं में उनकी योग्यता, शिक्षा तथा कौशल के मुताबिक वेतन तथा पैकेज देने की क्षमता नहीं है। इसलिए वे अच्छे पैकेज तथा सुख-सुविधाओं के लिए महानगरों या फिर विदेशों का रुख करते हैं। निजी कम्पनियां पैसा अवश्य देती हैं, लेकिन दिन-रात काम लेकर जान निकल कर रख देती हैं। साल-छह महीने के बाद भी छुट्टी नहीं दी जाती। माता-पिता तथा परिजन विवाह, शादियों, शुभ अवसरों तथा तीज-त्योहारों पर अपने लाडलों की प्रतीक्षा करते हैं। अगर किसी अवसर पर सीमित छुट्टी में घर पर पहुंच भी जाते हैं तो अपने ही बच्चे मेहमान बन कर ही आते हैं। आठ-दस दिन की छुट्टी में दो-दो दिन आने-जाने में, दो दिन घूमने-फिरने में, दो दिन सगे सम्बन्धियों से मिलने तथा दो दिन वापसी की तैयारियों में लग जाते हैं। इसलिए तीन दशक पहले ट्रकों पर लिखा हुआ रोजगार, परिवार के भरण पोषण का दर्द, मजबूरी तथा पीड़ा 'चन्दरेयां नोटां ने मेरा चन्न परदेसी कीता' के मायने अब समझ आते हैं।

इस वाक्य में वर्णित ड्राइवरों का दुःख-दर्द, पीड़ा तथा उनके परिजनों की वेदना वर्तमान परिदृश्य तथा परिप्रेक्ष्य में अब बेरोजगारों की पीड़ा तथा आज की व्यवस्था संचालकों की नीति एवं नीयत समझ आती है। यह कोई बहुत सामान्य बात नहीं है। इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार तथा मंथन होना चाहिए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकारों तथा व्यवस्थाओं की क्या जिम्मेदारी है? हमारा पढ़ा-लिखा तथा योग्य नौजवान रोजगार के लिए देस-परदेस तथा विदेश का रुख क्यों करता है? क्या भारतवर्ष में इस तरह के संसाधनों तथा योग्यतानुसार सैलरी पैकेज की उपलब्धता नहीं हो सकती? भारत से प्रतिभाओं का पलायन रोकना होगा।

गोबर के गुलगुले

देश में जब तक आज़ादी का अमृत काल नहीं उतरा था, आम जनता गुड़ से बने गुलगुले खाती थी। उस वक्त हिन्दी की एक मशहूर कहावत चलती नहीं दौड़ती थी- गुड़ खाए, गुलगुलों से परहेज़। लेकिन जब से भक्तों ने गुड़ की जगह गोबर खाना शुरू किया है, लगता है इस कहावत को बदलने का समय आ गया है। अब कहना हो तो कहना चाहिए- गोबर खाय, गुलगुलों से परहेज़। मुझे लगता है कि जो भक्त हैं, अगर उन्हें तनिक भी प्रेरित किया जाए तो वे गोबर के गुलगुले खाने से परहेज़ नहीं करेंगे। जब कई भक्त बाक़ायदा गोबर खाने के वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं तो वे इसके गुलगुले खाने से क्यों कर परहेज़ करेंगे। बस थोड़ी सी मोटीवेशन की ज़रूरत है। जब लोग बिना मोटीवेशन के ही इज़रायल के समर्थन में हमास से लडने गज़ा जा सकते हैं तो मोटीवेशन के बाद हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के लिए गोबर के गुलगुले भी खा सकते हैं। रही बात लद्दाख में चीनी क़ब्ज़े की तो उसे छुड़ाने के लिए किसी भी भक्त को अपने आपको वालंटियर करने की आवश्यकता नहीं। अपनी ज़मीन है, अगर किसी को दे भी दी तो हमारी मजरी। फिर हमारा तो इतिहास ही रहा है कि हम सभी मेहमानों का स्वागत पान पराग, क्षमा करें धूमधाम से करते हैं। हमारे लिए अतिथि देवो भवः हैं। चीन हमारा ख़ास मेहमान है। हमारा देश चीनी सामान का सबसे बड़ा आयातक है। हम अपनी दिवाली उनकी झालरों, लालटेन और लैम्पों से रौशन करते हैं। हमारे विदेश मंत्री एस. जयशंकर कहते हैं कि चीन हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम उससे पंगा नहीं ले सकते। जब किसी से पंगा लेने की हिम्मत न हो तो बेहतर होता है कि उसकी जी-हुज़ूरी की जाए। उसे झूला झुलाया जाए। फिर उसे मनचाहा नाम दे दिया जाए। क्या फर्क पड़ता है।

खाने तो गुलगुले ही हैं, वह भी गोबर के। जब लोग बिना किसी मोटीवेशन के सडक़ों पर गायों को खुला छोड़ सकते हैं और गोभक्ति की मोटीवेशन पर किसी विधर्मी की मॉब लिंचिंग कर सकते हैं तो क्या थोड़ी सी प्रेरणा मिलने अपनी गो-माता के सम्मान में गोबर के गुलगुले नहीं खा सकते। यूँ भी चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री सहित हमारे नेता जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि माननीयों सहित आम जन भी बिना किसी शर्मो-हया के गोबर खाने में मस्त हैं। प्रधानमंत्री का पद भले बड़ा हो, लेकिन उस पर बैठने वाले व्यक्ति का क़द इतना छोटा हो गया है कि उस पर बैठा आदमी अक्सर परी कथाओं के बौने की तरह अदृश्य हो उठता है। वह आँखे फाड़ कर देखने पर तभी नजऱ आता है जब उसकी ज़बान से निकलने वाला अगड़म-बगड़म लोगों के कान में गड़ता है। यह गोबर के गुलगुलों का ही प्रभाव है कि देश वैश्विक गुरू बनने के बाद आत्ममुग्धता की पींगें झूल रहा है और सम्मोहित लोग भूखे पेट राष्ट्रवाद के गीत गाते हुए झूम रहे हैं। भूख का इलाज भले गोबर न हो, लेकिन गोबर कैंसर का उपचार बेहद कारगर ढँग से कर सकता है।

मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर लोग राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार को सहयोग दें तो हो सकता है कि सरकार गोबर की प्रोसेसिंग के लिए श्रेष्ठतम वैश्विक प्रोद्यौगिकी वाले प्लांट लगाने के बाद गोबर के उत्तम गुणवत्ता वाले गुलगुलों का उत्पादन करे जो न केवल खाने में स्वादिष्ट हों, बल्कि सुपाच्य भी हों। इससे सरकार को अस्सी करोड़ लोगों को प्रति माह दिए जाने वाले निःशुल्क पाँच किलो राशन से भी छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। लोगों को घर बैठे रोजग़ार के जो अवसर प्राप्त होंगे, सो अलग। गुलगुले बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना की तजऱ् पर अन्य सरकारें गोबर खऱीद योजनाएं आरम्भ कर सकती हैं। अगर सरकार चाहे तो अपने चहेते व्यापारी मित्रों को गोबर प्रोद्यौगिकी के विकास और उन्नयन के लिए खरबों रुपये के आर्थिक पैकेज मुहैया करवा कर चीन ही नहीं, पूरे विश्व को गोबर के गुलगुलों के निर्यात के मामले में तो मात दे ही सकती है।

पीए सिद्धार्थ

दूसरी तिमाही में 100 बेसिस प्वाइंट तक घट सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था

अर्थशास्त्रियों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ सकती है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में साल-दर-साल 80-100 आधार अंकों तक सिकुड़ सकती है। इसकी वजह कमजोर बाहरी मांग बताई जा रही है। आपको बता दें कि दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े 30 नवंबर को जारी होंगे।

नई दिल्ली। भारत के अर्थव्यवस्था से जुड़ी चिंता की खबर सामने आ रही है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिल सकती है।

अर्थशास्त्रियों के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में साल-दर-साल 80-100 बीपीएस की गिरावट हो सकती है। इसका कारण बाहरी मांग में कमजोर होना बताया जा रहा है।

क्या है इस बार जीडीपी का अनुमान?

सरकार द्वारा दूसरी तिमाही के नतीजें 30 नवंबर को जारी होंगे। लेकिन नतीजों से पहले घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा के अर्थशास्त्रियों ने यह अनुमान लगाया था कि भारत की जीडीपी दूसरी तिमाही में 7 प्रतिशत हो सकती है, वहीं ब्रिटिश ब्रोकरेज बार्कलेज ने जीडीपी 6.8 प्रतिशत का अनुमान लगया है।

बार्कलेज के मुताबिक जीडीपी के 6.8 प्रतिशत पर रहने का अनुमान उपयोगिता क्षेत्रों (खनन और बिजली उत्पादन) और विनिर्माण, निर्माण और सार्वजनिक खर्च के कारण है।

इक्रा का अनुमान आरबीआई के एमपीसी से अधिक

इक्रा रेटिंग की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के मुताबिक दूसरी तिमाही में विकास दर 7 फीसदी रहेगी, जो आरबीआई की एमपीसी के अनुमान 6.5 फीसदी से अधिक होगी।

उनके मुताबिक दूसरी तिमाही में जीवीए वृद्धि दर घटकर 6.8 प्रतिशत हो जाएगी, जिसमें सेवा क्षेत्र की 8.2 प्रतिशत, कृषि की 3.5 प्रतिशत और उद्योग की 6.6 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है।

उन्होंने कहा, असमान वर्षा, साल भर पहले की कमोडिटी कीमतों के साथ अंतर कम होना, आम चुनावों के कारण सरकारी पूंजीगत व्यय की गति में संभावित मंदी, कमजोर बाहरी मांग और मौद्रिक सख्ती के संचयी प्रभाव से दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि कम होने की संभावना है।

इसके परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2024 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6 प्रतिशत रहने की संभावना है, जो कि वित्तीय वर्ष के लिए एमपीसी के 6.5 प्रतिशत के अनुमान से कम है।

क्या होती है जीडीपी?

एक वित्त वर्ष के दौरान किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी (जीडीपी) कहा जाता है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8 प्रतिशत थी।

इस राज्य में किसानों को मिलेगी दोगुना रकम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले- हर साल देंगे 12 हजार रुपये

केंद्र सरकार ने देश के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया है। इस स्कीम में किसानों को सालाना 6000 रुपये की राशि दी जाती है। अब पीएम मोदी ने एलान किया है कि राजस्थान के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 12000 रुपये की राशि दी जाएगी।

नई दिल्ली। पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। यह राशि किसानों को किस्तों में मिलती है। हर किस्त में किसान को 2,000 रुपये की राशि द जाती है। इसका मतलब है कि एक साल में किसानों को 3 किस्त मिलती है।

15 नवंबर 2023 को किसान के अकाउंट में पीएम किसान योजना की15वीं किस्त आ गई है। यह किस्त पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी में जारी की थी। इस योजना का लाभ 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलती है। इसका मतलब है कि पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त में सरकार ने 11 करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों के अकाउंट में जमा की है।

25 नवंबर 2023 को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाला है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एलान किया है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के पीएम किसान योजना के लाभार्थी को सालाना 12,000 रुपये दिये जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने किसानों से एमपीसी पर फसल खरीदने और बोनस देने का भी एलान किया है। ऐसे में अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है तो राजस्थान के पीएम किसान लाभार्थी को फायदा मिलने की संभावना है।

बीजेपी ने मध्य-प्रदेश के किसानों को भी पीएम किसान के तहत 12,000 रुपये की राशि देने का वादा किया है। आपको बता दें कि 6,000 रुपये की राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी और बाकी 6,000 रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

इनसाइड

निवेशकों के लिए खुल गया आईआरडीए का आईपीओ, जानिए प्राइस बैंड, लॉट साइज और अन्य डिटेल्स

जब भी किसी कंपनी को बड़े फंड की आवश्यकता होती है तो वह शेयर बाजार में लिस्ट होना पंसद करती है। शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए कंपनी को पहले अपना आईपीओ लॉन्च करना होता है। आज सरकारी कंपनी IREDA का आईपीओ भी निवेशकों के लिए खुलेगा।

नई दिल्ली। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए शेयर के साथ आईपीओ में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। शेयर बाजार में आईपीओ का सिलसिला अभी भी चालू है। आज सरकारी कंपनी IREDA का आईपीओ निवेशकों के लिए खुल गया है। यह आईपीओ 23 नवंबर 2023 (गुरुवार) तक ही है। इसका मतलब है कि आप इस आईपीओ में केवल 23 नवंबर 2023 तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA) का आईपीओ आज खुल गया है। कंपनी इस आईपीओ से 2,150.21 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहे हैं। IREDA के आईपीओ का प्राइस बैंड 30 रुपये से 32 रुपये निर्धारित किया गया है। आज सुबह 10.30 बजे तक कंपनी का आईपीओ 0.26 टाइम सब्सक्राइब हो गया था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 643 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बीएसई पर सोमवार देर रात अपलोड किए गए एक सर्कुलर के अनुसार, गोल्डमैन सैक्स, इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज (एशिया), सोसाइटी जेनरल, जीएएम स्टार इमर्जिंग इक्विटी, बीएनपी पारिबा आर्बिट्रेज, कॉप्थॉल मॉरीशस और मून कैपिटल ट्रेडिंग एंकर निवेशकों में से हैं।

खुलने वाला है टाटा ग्रुप का नया आईपीओ, प्राइस बैंड से लेकर लॉट साइज तक की सभी डिटेल्स

Tata Technologies IPO लगभग दो दशकों के बाद टाटा ग्रुप की कंपनी Tata Technologies का आईपीओ निवेशकों के लिए आ रहा है। Tata Technologies का आईपीओ 22 नवंबर 2023 (बुधवार) को निवेशकों के लिए खुलेगा। ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि वह इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करें या ना करें। 2004 में टीसीएस का आईपीओ खुला था।

नई दिल्ली। Tata Group IPO: शेयर बाजार में आईपीओ का सिलसिला अभी भी जारी है। अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको बता दें कि 22 नवंबर 2023 को यानी कि कल टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नॉलजीज (Tata Technologies) का आईपीओ खुलना वाला है। अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको एक बार टाटा टेक्नॉलजीज के आईपीओ के बारे में विस्तार से जान लेना चाहिए।

टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ

टाटा टेक्नॉलजीज का आईपीओ 22 नवंबर 2023 को खुलेगा और 24 नवंबर 2023 को बंद हो जाएगा। कंपनी इस आईपीओ के जरिये 3,042 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहे हैं। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 475 रुपये से 500 रुपये तय किया गया है। आज कंपनी के शेयर एंकर निवेशकों के लिए ओपन हुए हैं। आपको बता दें कि लगभग दो दशकों के बाद निवेशकों के लिए टाटा ग्रुप का आईपीओ आया है।

इससे पहले 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का आईपीओ ओपन हुआ था। आपको बता दें कि टाटा टेक्नॉलजीज का आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल के लिए है। कंपनी इस आईपीओ में 6.08 करोड़ (6,08,50,278) इक्विटी शेयरों को ओएफएस के लिए पेश करेगा। आपको बता दें कि टाटा टेक्नॉलजीज में टाटा मोटर्स (Tata Motors) की भी 11.4 फीसदी हिस्सेदारी है।

टाटा टेक्नोलॉजीज के इश्यू मूल्य दायरे के निचले स्तर ,890.4 करोड़ रुपये और ऊपरी स्तर 3,042.5 करोड़ रुपये है। जेएम फाइनेंशियल, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स और बोफा सिक्योरिटीज आईपीओ पर कंपनी को सलाह देने के लिए बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज के इक्विटी शेयर 5 दिसंबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होने की उम्मीद है।

टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में निवेशक करें या नहीं

कई एक्सपर्ट ने सलाह दिया है कि वह टाटा टेक्नॉलजीज के आईपीओ में निवेश करें। उनका कहना है कि भविष्य में कंपनी का प्रदर्शन काफी शानदार रहने वाला है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा टेक्नोलॉजीज अब एयरोस्पेस सेक्टर में अपना विस्तार करने की योजना बना रही है। ऐसे में कंपनी की ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है।

फर्जी जीएसटी बिल की पहचान कैसे करें? बहुत आसानी से कर सकते हैं असली और नकली बिल पहचान

GST Bill जब भी हम कोई शॉपिंग करते हैं तो हमें जीएसटी बिल लेना चाहिए। जीएसटी एक तरह का टैक्स है। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने जीएसटी बिल को लागू किया था। टैक्स चोरी को रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया था। कई सप्लायर फर्जी जीएसटी बिल जारी करते हैं। इस आर्टिकल मे जानते हैं कि फर्जी और असली जीएसटी बिल के बीच क्या अंतर है?

नई दिल्ली। गुड्स और सर्विस टैक्स सिस्टम को लागू करने का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सुचारु रूप से चलाना। कई लोग टैक्स चोरी करते थे या फिर लोगों से टैक्स के नाम पर ज्यादा राशि लेते थे। ऐसे में इस तरह के फर्जीवाड़ा पर नकेल कसने के लिए जीएसटी बिल लागू किया गया था।

वर्तमान में कई छोटे कारोबारी फर्जी जीएसटी बिल देकर अपने ग्राहकों को ठगते हैं। इस प्रकार की ठगी से सावधान रहने के लिए हमें पता होना चाहिए कि असली और फर्जी जीएसटी बिल में क्या अंतर है?

जीएसटी इनवॉयस क्या है?

जीएसटी इनवॉयस एक तरह का बिल होता है। यह बिल सप्लायर द्वारा सामान या फिर सर्विस देने पर दिया जाता है। यह डॉक्यूमेंट होता है कि सप्लायर ने ग्राहक को क्या सामान कितनी राशि में दिया है और उसपर कितना टैक्स लगाया है। इस बिल में सप्लायर का नाम, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जानकारी, खरीद की तारीख, डिस्काउंट और बाकी जानकारी होती है।

फेक जीएसटी इनवॉयस क्या है?

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार फर्जी जीएसटी बिल या इनवॉयस में सामान की सही जानकारी नही होती है। यह बिल टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रींग (गबन), फेक बुकिंग के लिये किया जाता है। इसके अलावा इनकम क्रेडिट को कैश करने के लिए भी फर्जी बिल जनरेट किया जाता है। अब ऐसे में सवाल है कि आप असली और फर्जी जीएसटी बिल को कैसे पहचानें?

फेक जीएसटी बिल को कैसे पहचानें

फेक जीएसटी बिल को पहचाने का आसान तरीका है उसका जीएसटी नंबर। जीएसटी बिल पर 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है। इस नंबके पहले दो डिजिट में स्टेट कोड होता है और बाकी के 10 डिजिट में सप्लायर या दुकानदार का पैन नंबर होता है। वहीं 13वां डिजिट पैन धारक की इकाई होता है और 14वां स्थान पर पर 'Z' और आखिरी में 'checksum digit' होता है।

आप जीएसटी नंबर के फॉरमेट से भी असली और नकली जीएसटी नंबर की पहचान कर सकते हैं।

आप जीएसटी वेबसाइट पर भी जीएसटी बिल को चेक कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर जीएसटी दर्ज करें इसके बाद आपको स्क्रीन पर सप्लायर की डिटेल्स शो हो जाएगी।

जीएसटी फ्रॉड के लिए कहां शिकायत करें

अगर आपके पास कभी फेक जीएसटी बिल आ जाता है तो आप जीएसटी के अधिकारिक पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

फेस्टिव सीजन के बाद महंगा हुआ गोल्ड और सिल्वर, चेक करें अपने शहर के लेटेस्ट रेट

परिवहन विशेष न्यूज

फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। आज भी सोने और चांदी के दाम में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ऐसे में अगर आप गोल्ड या स्लिवर खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको एक बार अपने शहर का लेटेस्ट रेट जरूर चेक करना चाहिए। आज दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 62020 रुपये है।

नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन खत्म हो गया है और कुछ दिन के बाद वेडिंग सीजन (Wedding Season) शुरू हो जाएगा। इस सीजन के शुरू होने से पहले सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। आज भी सोने और चांदी के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में अगर आप गोल्ड या सिल्वर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको अपने शहर के लेटेस्ट रेट के बारे में जरूर चेक करना चाहिए।

महंगा हुआ गोल्ड

मंगलवार को वायदा कारोबार में सोने की कीमत 353 रुपये बढ़कर 61,010 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 353 रुपये या 0.58 प्रतिशत बढ़कर 61,010 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 7,262 लॉट का कारोबार हुआ।

वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में सोना वायदा 0.71 प्रतिशत बढ़कर 1,994.30 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस हो गया।

चांदी में आई तेजी

वायदा कारोबार में मंगलवार को चांदी की कीमत 289 रुपये बढ़कर 72,933 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध 289 रुपये या 0.4 प्रतिशत बढ़कर 14,865 लॉट में 72,933 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया।

वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में चांदी 0.55 प्रतिशत बढ़कर 24.09 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।

आपके शहर में क्या है सोने की कीमत

गुड रिटर्न वेबसाइट के अनुसार

दिल्ली में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 62,020 रुपये है।

मुंबई में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 62,020 रुपये है।

कोलकाता में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 62,020 रुपये है।

चैन्नई में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 62,510 रुपये है।

बेंगलुरु में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 62,020 रुपये है।

हैदराबाद में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 62,020 रुपये है।

चंडीगढ़ में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 62,170 रुपये है।

जयपुर में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 62,170 रुपये है।

पटना में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 62,070 रुपये है।

लखनऊ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 62,170 रुपये है।

कोंग्रेस नेता प्रसाद हरिचंदन ने कहा कि लोगों को पुरी जाने से रोकना संविधान के खिलाफ है

मनोरंजन सासमल ,ओड़िशा

भुबनेस्वर: नबान्न हुसैन शाह की जिद के आगे राज्य सरकार की जिद हार गई। नबां हुसैन शाह ने कहा कि दंड में कोई हरि नाम नहीं ले सकता। इसी तरह राज्य सरकार भी उन्हीं कदमों पर चल रही है. लोगों को पुरी जाने से भी रोककर सरकार ने खुद को संविधान विरोधी और कानून विरोधी साबित कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रसाद हरिचंदन ने आज सरकार पर निशाना साधा है.प्रसाद हरिचंदन ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कार्तिक माह में लोग देश-विदेश के विभिन्न हिस्सों से पुरी में जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं. ठाकुर के दर्शन करना हमारा धार्मिक, संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त अधिकार है। इस पर प्रतिबंध लगाना कानून के खिलाफ है. सरकार द्वारा लगाए गए एकाधिकार ने केवल भक्तों और भगवान के बीच एक बाधा पैदा की है। यह कानून के खिलाफ है। वे हमारे संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन कर रहे हैं।

कल श्रिमन्दिर् के सामने भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिली. सुबह आए श्रद्धालु 10 बजे तक लाइन में खड़े नजर आए। भीड़ के कारण श्रद्धालुओं को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा और परेशान होना पड़ा। कुछ लोग बीमार भी थे. फिर भी, एक बूढ़ी औरत ने उसे लाइन से बचाने के लिए चिल्लाया। इसे देखते हुए श्रीमंदिर के मुख्य प्रशासक रंजन कुमार दास ने बुजुर्ग और बीमार लोगों से पुरी नहीं आने का अनुरोध किया है.उन्होंने कहा, जहां भी उन्हें बुलाया जाएगा भगवान उनकी सुनेंगे। उनसे अनुरोध है कि वे बहुत अधिक उत्साह में भीड़ में न आएं। ऐसे समय आना बेहतर है जब भीड़ कम हो। सभी से अनुरोध है कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रूचि लेकर ठाकुर जी के दर्शन हेतु आयें।

गौरतलब है कि आज कोई एक दिन नहीं, पुरी बडदांड़ में महीनों से ऐसी ही भीड़ लगी रहती है. लेकिन सरकार, प्रशासन, पुलिस इसे नजरअंदाज करती रहती है. अब श्रद्धालु केवल सिंह द्वार से ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। बताया जाता है कि श्रीमन्दिर् की परिक्रमा परियोजना के कारण अन्य तीन दरवाजे बंद होने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है।

इसके विपरीत, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मंदिर की स्थिति को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है. श्रीजीयू के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की हालत देखकर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल काफी दुखी हैं. उन्होंने कहा, अगर परिक्रमा परियोजना के निर्माण के लिए एक दरवाजा बंद रखा जाता तो बाकी तीन दरवाजे खुल जाते और श्रद्धालु दर्शन कर पाते.

कांग्रेस गरीबों और आस्था का सम्मान नहीं कर सकती : योगी आदित्यनाथ

भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में कि विजय संकल्प चुनावी सभा

परिवहन विशेष-अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के चलते मंगलवार दोपहर पहली बार शाहपुरा एवं भीलवाड़ा मे भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में पहुंचे, भीलवाड़ा में भाजपा जिला कार्यालय के पास, प्रस्तावित बस स्टैंड में चुनावी सभा के मंच पर पहुंचते ही भीलवाड़ा भाजपा प्रत्याशी विट्ठल शंकर अवस्थी, लादू लाल पितलिया, उदयलाल भड़ाना, अजमेर संभाग चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह, सांसद सुभाष बहेड़िया, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ,अतर सिंह भडाना, कालू लाल गुर्जर, राकेश पाठक, बरजी देवी भील, रिंकू कंवर ने 101 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया योगी करीब दो घंटा देरी से कार्यक्रम में पहुंचे

संतो ने आशीर्वाद ले गोटा भेंट किया

भीलवाड़ा के प्रमुख संतो बाबू गिरी जी महाराज, बनवारी शरण जी कठियावाला ,मुरली शरण जी, रामायणी महाराज, लाल बाबा ने योगी आदित्यनाथ के चरण छूकर उन्हें हनुमान जी का गोटा भैट किया

भीलवाड़ा सहाड़ा एवं मांडल विधानसभा क्षेत्र की संयुक्त चुनावी सभा मैं बुलडोजर बाबा के नाम से फेम योगी आदित्यनाथ ने जय भवानी, करणी माता, राम राम सा

भारत माता कि जय से संबोधन शुरू किया उन्होंने कहा कि आतंकवाद नक्सलवाद और भ्रष्टाचार की समस्या कांग्रेस की देन है कांग्रेस समस्या देती रही है मोदी ने इसका रास्ता निकाला है कांग्रेस सामान्य और गरीब परिवार को योजनाओं से वंचित करती है देश के विकास में सभी लोग योगदान देते हैं देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के नौजवानों किसानो का है योगी ने कहा कि मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है इसका परिणाम क्या रहा 4 करोड़ परिवारों को आवास मिला, 10 करोड़ गरीबों को निशुल्क गैस कनेक्शन मिला,देश के

अंदर 50 करोड लोगों को आयुष्मान भारत से ₹5 लाख तक का मेडिकल की सुविधा का लाभ मिला, 7 करोड़ गरीबों तक के घर में हर घर नल योजना चालू हुई 4 करोड लोगों को बिजली कनेक्शन मिले, 80 करोड लोगों को 3 वर्ष से निशुल्क राशन दिया जा रहा है कोरोना जैसी महामारी के लिए दो सबसे प्रभावशाली वैक्सीन भारत में फ्री दी गई उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर नहीं बनवा पाई ,ना रोजगार दे सकती है, ना भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकती है ना अत्याचार रोक सकती है राजस्थान भ्रष्टाचार और महिला अपराध, साइबर अपराध, बिजली दरो ,सभी कामों में राजस्थान सरकार नंबर एक पर है योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में पीछे हैं डबल इंजन की सरकार होती है तो माफिया का क्या होता है यह तो आप जानते हो कांग्रेस गरीबों का कल्याण नहीं कर सकती और उसकी आस्था का भी सम्मान नहीं कर सकती उत्तराखंड केदारपुर में आस्था का सम्मान दिखाई दे रहा है अयोध्या में भी तो राम मंदिर बन रहा है मतलब यह ही है भाजपा की डबल इंजन की सरकार आएगी बिजली और पेट्रोल डीजल की दरें सबसे ज्यादा राजस्थान में है पेपर लीक राजस्थान में ,मंडी टैक्स या सबसे ज्यादा लिया जा रहा है बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिलने का कारण सबसे ज्यादा आत्महत्या भी राजस्थान में हो रही है जहां राजस्थान सरकार रामनवमी धार्मिक जुलूसों पर कर्फ्यू लगाती है वही उत्तर प्रदेश में चार करोड लोगों की शांतिपूर्ण कावड़ यात्रा बिना किसी व्यवधान के जारी रहती है योगी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है भारत का सम्मान बढ़ रहा है योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य में 5 अन्य रेलिया को भी संबोधित किया शाहपुरा, मांडलगढ़ एवं जहाजपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशियों के लिए योगी ने नया बस स्टैंड शाहपुरा में आमसभा को संबोधित किया

आतंकवाद पर अंकुश

नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही पिछले 9 वर्षों में आतंकवाद ही नहीं आतंकवाद के आकाओ को भी ठिकाने लगाया है

विश्व में भारत अगले तीन वर्षों में तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी

कांग्रेस के समय भारत विश्व में 10 से 12वी अर्थव्यवस्था मैं गिना जाता था विगत 9 वर्षों में मोदी सरकार के बाद विश्व में पांचवी अर्थव्यवस्था में भारत का नाम है मोदी सरकार के नेतृत्व में अगले 3 वर्षों में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। सभा का संचालन राकेश ओझा ने किया।

(बीपीएम) का भुज में 26 को 3सरा अधिवेशन

परिवहन विशेष।एसडी सेठी। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के संगठन भारतीय पेंशनर्स मंच- (राष्ट्रवादी) का तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन 26 नवंबर को गुजरात के भुज में आयोजित किया जा रहा है। मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद पराशर ने बताया कि पेंशनर्स मंच के संस्थापक वी एस यादव की अध्यक्षता में वागड 2, चौबीसी, जैन धर्मशाला म आयोजित होने वाले इस अधिवेशन में देश के विभिन्न राज्यों से 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगें। वहीं मंच के चेयरमैन वी एस यादव ने अधिवेशन के मुद्दो की बावत बताया कि पेंशनधारको की मुख्य मांगों में पेंशन को इंकम-टैक्स से मुक्त करने, वहीं 65 वर्ष की उम्र होने पर 20 फीसदी पेंशन में बढोतरी के अलावा 80 की उम्र होने पर 100 फीसदी की पेंशन में बढोतरी करने पर चर्चा की जाएगी, इसके अलावा सीनियर सिटिजन को रेल भाड़े में मिल रही छूट को खत्म करने के आदेश को वापस लेने, के अलावा कोरोना महामारी के दौरान पेंशनधारियों के 18 महा के मंहगाई राहत को फ्रिज करने वाले जैसे आदेश को वापस लेने संबधित मुद्दो पर चर्चा के बाद एक्शन लेने पर प्रस्ताव पारित किए जाएगें। प्रवक्ता विनोद पराशर ने बताया कि अधिवेशन के दौरान संगठन के कर्मठ कार्यकर्ताओ को 'पेंशनर्स रत्न सम्मान 'से भी अलंकृत किया जाएगा। संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होगी।

दिल्ली सड़क हादसे में बिखरा परिवार: स्कूटी सवार को कार ने मारी टक्कर, पति-बच्चे की मौत, पत्नी समेत दो भर्ती

दिल्ली के राजौरी गार्डन थाना इलाके में एक स्कूटी सवार परिवार को कार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में सभी लोग घायल हैं। सभी घायलों को घटना के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। एक कार सवार ने स्कूटी से जा रहे परिवार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में परिवार घायल हो गया। यह घटना राजौरी गार्डन इलाके की बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक, राजौरी गार्डन थाना इलाके में 20 और 21 नवंबर की आधी रात को करीब एक बजे सड़क हादसे की सूचना मिली। घटना में स्कूटी को कार ने पीछे से टक्कर मार दी। स्कूटी पर पति-पत्नी और दो बच्चे थे। स्कूटी पर सवार सभी लोग घायल हैं। सभी घायलों को घटना के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि, हादसे में घायल दिनेश वसन और आठ साल के बच्चे दकक्ष की मौत हो चुकी है। वहीं पत्नी और आठ साल के दूसरे बच्चे प्रयान का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस जांच में जुट गई है। सभी कैमरों को खंगाला जा रहा है। आरोपी चालक की तलाश की जा रही है।

रेल यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, कैंसिल हुई 31 जोड़ी ट्रेनें

नई दिल्ली। सर्दी में यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी उत्तर रेलवे ने लगभग तीन माह तक 31 जोड़ी ट्रेनें निरस्त करने की घोषणा कर दी है। इनमें से कई ट्रेनें एक दिसंबर से फरवरी तक और कुछ मार्च पहले सप्ताह तक नहीं चलेंगी। 15 जोड़ी ट्रेनों के फेरे कम कर दिए गए हैं। तीन जोड़ी ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त करने का फैसला किया गया है।

निरस्त की गई मुख्य ट्रेनें

ट्रेन- कब तक निरस्त रहेगी
लिच्छवी एक्सप्रेस- तीन दिसंबर से दो मार्च
शहीद एक्सप्रेस- पांच दिसंबर से 29फरवरी
नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस- तीन दिसंबर से 29 फरवरी
लखनऊ डबल डेकर एक्सप्रेस- एक दिसंबर से 29 फरवरी
आनंद विहार टर्मिनल-लालकुआं एक्सप्रेस-पांच दिसंबर से 29 फरवरी
अमृतसर-टाटा नगर एक्सप्रेस-छह दिसंबर से 28 फरवरी
आनंद विहार टर्मिनल-गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस- छह दिसंबर से 28 फरवरी
आनंद विहार टर्मिनल- बलिया क्लोन एक्सप्रेस-छह दिसंबर से 28 फरवरी
हजरत निजामुद्दीन-अंबिकापुर विशेष सुपरफास्ट-पांच दिसंबर से 27 फरवरी
नई दिल्ली-सोगरिया (कोटा) एक्सप्रेस-एक दिसंबर से 29 फरवरी
आनंद विहार-कामख्या एक्सप्रेस- आठ दिसंबर से 29 फरवरी
झारखंड स्वर्ण जयंति एक्सप्रेस-पांच दिसंबर से एक मार्च
आनंद विहार टर्मिनल- संतरागाछी एक्सप्रेस-पांच दिसंबर से 27 फरवरी
इन ट्रेनों के फेरे कम किए गए
ट्रेन- जिस दिन निरस्त रहेगी
कैफियत एक्सप्रेस- पुरानी दिल्ली से बुधवार व शनिवार तथा आजमगढ़ से बृहस्पतिवार और रविवार।

अमृतसर मत्स्य पालन विभाग द्वारा मनाया गया विश्व मत्स्य पालन दिवस

परिवहन विशेष न्यूज

अमृतसर, (साहिल बेरी) दुनिया भर में मनाए जाने वाले विश्व मत्स्य पालन दिवस के सिलसिले में मत्स्य विभाग अमृतसर द्वारा सिमरन पैलेस अमृतसर में यह दिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया जिसमें पंजाब के लगभग डेढ़ सौ मछलियाँ विभिन्न जिलों के किसानों, मछली विक्रेताओं और ठेकेदारों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। सबसे पहले गुरबीर सिंह वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, अमृतसर ने विश्व मत्स्य पालन दिवस पर गुरुमीत सिंह खुदिया कैबिनेट मंत्री पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास पंजाब द्वारा भेजे गए संदेश के बारे में जानकारी दी जिसमें कैबिनेट मंत्री ने इस दिन मछली पालकों को संबोधित किया और बधाई दी और कहा कि पंजाब सरकार राज्य में मछली पकड़ने के उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता

प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एस। गुरमीत सिंह खुड़िया ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य मछली पालन के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने किसानों से मछली पालन के व्यवसाय से जुड़कर विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की. इसके बाद मैडम सुप्रिया कंबोज मत्स्य अधिकारी अमृतसर और विशाल शर्मा मत्स्य अधिकारी पठानकोट ने विभाग में चल रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर महेंद्रपाल सिंह सहायक डायरेक्टर मत्स्य पालन तरनतारन, दलजीत सिंह सहायक निदेशक मत्स्य पालन गुरदासपुर, राजीव कुमार सहायक निदेशक मत्स्य पालन होशियारपुर, गुरविंदर सिंह सहायक निदेशक मत्स्य पालन पठानकोट, विक्रमप्रीत सिंह सहायक निदेशक मत्स्य पालन कपूरथला, गुरबीर सिंह वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, अमृतसर सरबजीत सिंह वरिष्ठ मत्स्य पालन अधिकारी राजासांसी, आकाशदीप सिंह मत्स्य अधिकारी, मंगत राम वरिष्ठ सहायक, सचलीन बाजवा, हीरा सिंह, मैडम हरविंदर कौर, प्रकाश चंद, कंवलजीत सिंह सेखों आदि भी उपस्थित थे।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष को चुनाव आयोग का कारण बताओ नोटिस, सीएम केजरीवाल की छवि खराब करने को लेकर AAP ने की थी शिकायत

अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने के आरोप पर चुनाव आयोग ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आप प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत में भाजपा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर बेतुकी सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। शिकायत में आप ने भाजपा के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने यह नोटिस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने को लेकर जारी किया है। बता दें कि सोमवार को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के नेतृत्व में आप का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के पास पहुंचा था। आप प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत में भाजपा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर बेतुकी सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

भाजपा के खिलाफ कार्रवाई का किया अनुरोध

आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चुनाव आयोग में शिकायत देने पहुंचे। राघव चड्ढा ने कहा कि आप के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत का संज्ञान लेने और भाजपा के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने 05 नवंबर की एक पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने की कोशिश करने के लिए घटिया सामग्री का उपयोग कर रही है। वे उनके चरित्र के हनन की कोशिश कर रहे हैं। खास बात है कि पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अरविंद केजरीवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

अमृतसर अजनाले के सर्वांगीण विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी

ये शब्द कैबिनेट मंत्री श्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अजनाला हलके में निर्माणाधीन विभिन्न सड़कों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने के बाद व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अजनाला के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और इससे लोगों को काफी सुविधा होगी।

अमृतसर (साहिल बेरी) धालीवाल ने अजनाले में निर्माणाधीन सड़कों का मौके पर निरीक्षण किया, जिसके चलते अजनाला को पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, लेकिन अब अजनाले के चारों ओर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। और अजनाला के सर्वांगीण विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। ये शब्द कैबिनेट मंत्री श्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अजनाला हलके में निर्माणाधीन विभिन्न सड़कों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने के बाद व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अजनाला के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और इससे लोगों को काफी सुविधा होगी. उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा पारो साहिब से लेकर मत्तेवाल से लेकर विछोआ तक 9 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है और इस सड़क को 18 फुट चौड़ा भी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सड़क पर 6.5 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. उन्होंने कहा कि वे स्वयं निर्माणाधीन सड़कों का

निरीक्षण कर रहे हैं और ठेकेदार को सख्त निर्देश दिये हैं कि विकास के नाम पर कोई समझौता नहीं किया जायेगा. उन्होंने कहा कि एक साल के अंदर पूरा बदला हुआ शहर दिखेगा. उन्होंने कहा कि अजनाले के सर्वांगीण विकास के लिए पंचायत घर, पशु चिकित्सालय आदि कार्य तेजी से किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रावी नदी में पानी के कारण स्पर्म खराब हो गया है. इन पर 10 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. एसः धालीवाल ने आगे कहा कि अजनालवासियों के लिए सबसे बड़ा तोहफा कल मिलने जा रहा है. उन्होंने कहा कि अजनाले से फतेहगढ़ चूड़ी-रामदास रोड की मरम्मत का टेंडर कल खुलेगा, जिस पर 55 करोड़ रुपये की लागत आएगी. उन्होंने कहा कि अजनाले के स्कूलों के लिए 27 करोड़ 85 लाख रुपये खर्च कर स्कूलों को नया लुक दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब के चार-आयामी विकास को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है और राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा और खेलों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल विपक्षी दलों के पास बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है. एसः धालीवाल ने कहा कि हमारी सरकार आम लोगों की सरकार है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान राज्य के लोगों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं ताकि पंजाब को रंगला पंजाब बनाया जा सके. कैप्शनः कैबिनेट मंत्री श्री कुलदीप सिंह धालीवाल निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण करते हुए।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023